

अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे।

RNI No :- DELHIN/2023/86499  
DCP Licensing Number :  
F.2 (P-2) Press/2023

वर्ष 02, अंक 280, नई दिल्ली। गुरुवार, 19 दिसम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

03 प्रत्याशी की जल्द जारी होगी लिस्ट, भाजपा ने घोषित की चुनाव कमेटी

06 पुरुष प्रताडना का औचित्य

08 अफसर राज खतम : सांसदों और विधायकों के लिए खुलेगी विशेष सेल

## प्रदूषण नियंत्रण के नाम से अब आम जनता की जेब पर बढ़ेगा और अधिक बोझ

संजय बाटला

नई दिल्ली। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि दिल्ली नगर निगम 19 दिसंबर को फिर से सदन में दिल्ली में पार्किंग शुल्क को दोगुना करने का प्रस्ताव पेश करेगी।

दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की जेब पर असर पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर से पार्किंग के दाम दो गुना करने का प्रस्ताव सदन में आया। प्रस्ताव के तहत पार्किंग के दाम को दो गुना किया जाए, दिल्ली भर में एमसीडी के 450 से अधिक पार्किंग स्थल हैं, जहां इन्हें लागू किया जाएगा।

एमसीडी ने पहले भी पार्किंग शुल्क को चार गुना बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया था लेकिन वह पास नहीं हो पाया था। निगम ने अब पार्किंग के दाम चार गुना से दो गुना करने का प्रस्ताव रखा है। उम्मीद है कि यह प्रस्ताव इस बार पास हो सकता है। दिल्ली नगर निगम की बैठक 19 दिसंबर को होगी। एमसीडी ने लोगों से आग्रह किया है कि लोग कम से कम निजी वाहनों का इस्तेमाल करें।

अगर यह प्रस्ताव सदन में पास हो जाता है तो जाने क्या होंगे नए



पार्किंग चार्ज अब तक दिल्ली नगर निगम कार पार्किंग के लिए 20 रुपये प्रतिघंटा और दो पहिया वाहनों की पार्किंग के लिए 10 रुपये प्रति घंटा लेती है। अगर इस बार सदन से एमसीडी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो पार्किंग के दाम बढ़कर कार पार्किंग के लिए 40 रुपये प्रति घंटा और दो पहिया वाहनों के लिए 20 रुपये प्रतिघंटा चार्ज

हो जाएंगे। साथ ही आप को बता दे की 24 घंटे के लिए दो पहिया वाहनों से पार्किंग शुल्क 50 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 100 रुपये ही वसूला जाएगा।

एमसीडी का मानना है की दिल्ली के लोगों को बड़े पार्किंग दामों से फर्क नहीं पड़ता एमसीडी का कहना है की दिल्ली में पार्किंग के दाम इसलिए

बढ़ाए जा रहे हैं जिससे लोग निजी वाहनों के इस्तेमाल का प्रयोग करने से बचें पर जमीनी स्तर पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि, जमीनी स्तर पर इसका कोई फर्क नहीं दिखता। आपकी जानकारी के लिए बता दें एनडीएमसी ने पार्किंग के भाव चार गुणा बढ़ा दिए हैं उसके बावजूद कॉन्ट्रैक्ट प्लेस सहित अन्य पार्किंग में वाहनों की लंबी-लंबी कतारें अब भी

दिखाई देती हैं। लोग अब भी पहले की तरह ही वाहनों से निकल रहे हैं।

अब आप ही बताएं जब दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग दिल्ली जनता को जबरन के अनुसार सुखद सुरक्षित सार्वजनिक सवारी उपलब्ध करवाने में पूरी तरह असफल है तो जनता के पास

1. निजी वाहनों का प्रयोग करने के अलावा और क्या हल है ?  
2. क्या आज से 50 साल पहले की तरह पैदल सड़कें नापे या  
3. आज के तेज चलते युग में काम धाम और नौकरी छोड़कर घर बैठ जाए ?

सार्वजनिक सवारी सेवा उपलब्ध करवाने में जीरो और निजी वाहनों के प्रयोग पर जान बूझकर मोटी दर का पार्किंग शुल्क, कहा का न्यायिक आदेश

अपनी गलतियों और खामियों का खामियाजा की सजा जनता के सिर पर और जुमाना/ अतिरिक्त शुल्क लगा कर राजस्व में इजाफा यही है आज दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग का निराला दायित्व कितना न्यायिक, जन प्रिय और जनहित में ?

## येलो लाइन में मेट्रो की टाइमिंग में बड़ा बदलाव, कई रुटों के लिए बदला समय

दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक मेट्रो के परिचालन समय में बदलाव किया गया है। समयपुर बादली से मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम के लिए सुबह में एक घंटा देरी से मेट्रो मिलेगी। मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम से समयपुर बादली के लिए आखिरी ट्रेन रात साढ़े नौ बजे के बाद उपलब्ध नहीं होगी।

नई दिल्ली। मेट्रो फेज चार के कॉरिडोर के निर्माण के कार्य के कारण दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने येलो लाइन पर मेट्रो परिचालन के समय में थोड़ा बदलाव किया है।

सुबह एक घंटा देरी से मिलेगी ट्रेन : इससे बुधवार से 28 दिसंबर तक समयपुर बादली से मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम के लिए सुबह में एक घंटा देरी से मेट्रो उपलब्ध होगी।

आखिरी ट्रेन रात साढ़े नौ बजे तक मिलेगी : वहीं मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम से समयपुर बादली के लिए आखिरी ट्रेन रात साढ़े नौ बजे के बाद उपलब्ध नहीं होगी।

अंतिम ट्रेन रात में 10:45 बजे उपलब्ध होगी : डीएमआरसी ने एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है। जिसमें कहा गया है कि समयपुर बादली से मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के लिए पहली ट्रेन सुबह 7:02 से मिलेगी और अंतिम ट्रेन रात में 10:45 बजे उपलब्ध होगी। मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम से समयपुर बादली के लिए आखिरी ट्रेन रात में 9:30 बजे उपलब्ध होगी।

पहली ट्रेन सुबह 7:07 बजे मिलेगी : जहांगीरपुरी से समयपुर बादली के लिए पहली ट्रेन सुबह 7:07 बजे और रात में अंतिम ट्रेन 10:45 बजे उपलब्ध होगी। वहीं जहांगीरपुरी से मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के लिए पहली ट्रेन सुबह 6:10 बजे उपलब्ध होगी।

रिठाला के लिए आखिरी ट्रेन रात 10:45 बजे तक ही मिलेगी : इसके अलावा रेड लाइन पर बुधवार से 31 दिसंबर तक शहीद स्थल नया बस अड्डा गाजियाबाद मेट्रो स्टेशन से रिठाला के लिए आखिरी ट्रेन रात 11 बजे की जगह रात 10:45 बजे ही उपलब्ध होगी। केशव पुरम से रिठाला के लिए आखिरी ट्रेन रात 11:30 बजे उपलब्ध होगी।



## सड़क सुरक्षा: नाबालिग चालकों की समस्या और समाधान पर विचार

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण नाबालिग चालकों का वाहन चलाना है। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 199A इस मामले में सख्त प्रावधान करती है। इसके तहत, यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उस वाहन के मालिक को ₹25,000 का जुर्माना भरना पड़ता है। साथ ही, वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है और तीन साल तक की जेल हो सकती है। नाबालिग का ड्राइविंग लाइसेंस भी 25 वर्ष की आयु तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है।

हालांकि, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इस प्रावधान के अनुपालन में कई व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करती है। नाबालिग की उम्र की पुष्टि के लिए स्कूल से प्रमाण लेना और मामलों को किशोर न्यायालय तक ले जाना समय-साध्य प्रक्रिया है। इसलिए, अक्सर 5/180 के तहत चालान काटा जाता है, जिसमें र अनधिकृत व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना का आरोप लगाकर ₹5,000 का जुर्माना लगाया जाता है।

मौजूदा समस्या पर विचार

यह स्पष्ट है कि ट्रैफिक पुलिस प्रक्रिया को सरल रखने के लिए कम सख्त प्रावधान का उपयोग करती है। हालांकि, यह समाधान सड़क सुरक्षा पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों को अनदेखा करता है। नाबालिग चालकों को कम जुर्माने के साथ छोड़ देना, सड़क पर उनकी बढ़ती उपस्थिति को प्रोत्साहित कर सकता है।

समाधान: पहचान और तकनीकी उपाय

जगमोहन सिंह द्वारा सुझाए गए एक विचार पर चर्चा करते हुए, यह सुझाव दिया गया है कि ट्रैफिक पुलिस मौके पर ही नाबालिग को पहचान के लिए कुछ त्वरित और प्रभावी कदम उठा सकती है। उदाहरण के तौर पर:

आधार कार्ड या पहचान पत्र की मांग



यदि वाहन चलाने वाला व्यक्ति अपनी उम्र को लेकर विवाद में है, तो पुलिस उसका आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र तुरंत देख सकती है।

फोटो और दस्तावेज कीकरण

वाहन और चालक की फोटो खींचकर इसे प्रमाण के तौर पर रखा जा सकता है। इसे कानूनी कार्रवाई के लिए मजबूत सबूत माना जा सकता है।

डिजिटल समाधान

पुलिस अपने डिजिटल उपकरणों में एक ऐप या सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकती है, जिससे मौके पर ही आधार कार्ड या अन्य प्रमाण पत्र की वैधता जांची जा सके।

सार्वजनिक जागरूकता अभियान

नाबालिगों के वाहन चलाने से जुड़े खतरों और इसके कानूनी परिणामों पर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। माता-पिता और स्कूलों को इस दिशा में शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है।

सरकार और समाज की भूमिका

यह समस्या केवल कानून और पुलिस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की भी जिम्मेदारी है। यदि सरकार और नागरिक इस मुद्दे को गंभीरता से लें, तो इसे रोका जा सकता है। सरकार को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े प्रावधान लागू करने के साथ-साथ पुलिस विभाग को आधुनिक उपकरण और संसाधन प्रदान करने चाहिए।

इसके अतिरिक्त, माता-पिता को यह सुनिश्चित करना

चाहिए कि वे अपने बच्चों को कम उम्र में वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित न करें। स्कूलों को भी बच्चों और उनके अभिभावकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

निष्कर्ष

नाबालिग चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जागरूकता का प्रसार सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। ट्रैफिक पुलिस को कानून के पालन में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक सहायता दी जानी चाहिए। साथ ही, नागरिकों को भी यह समझना होगा कि सड़क पर सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।

## दिल्ली में अब केवल इन वाहनों को ही मिलेगा पेट्रोल-डीजल, गाड़ियों के कट रहे चालान; हो रही जब्ती

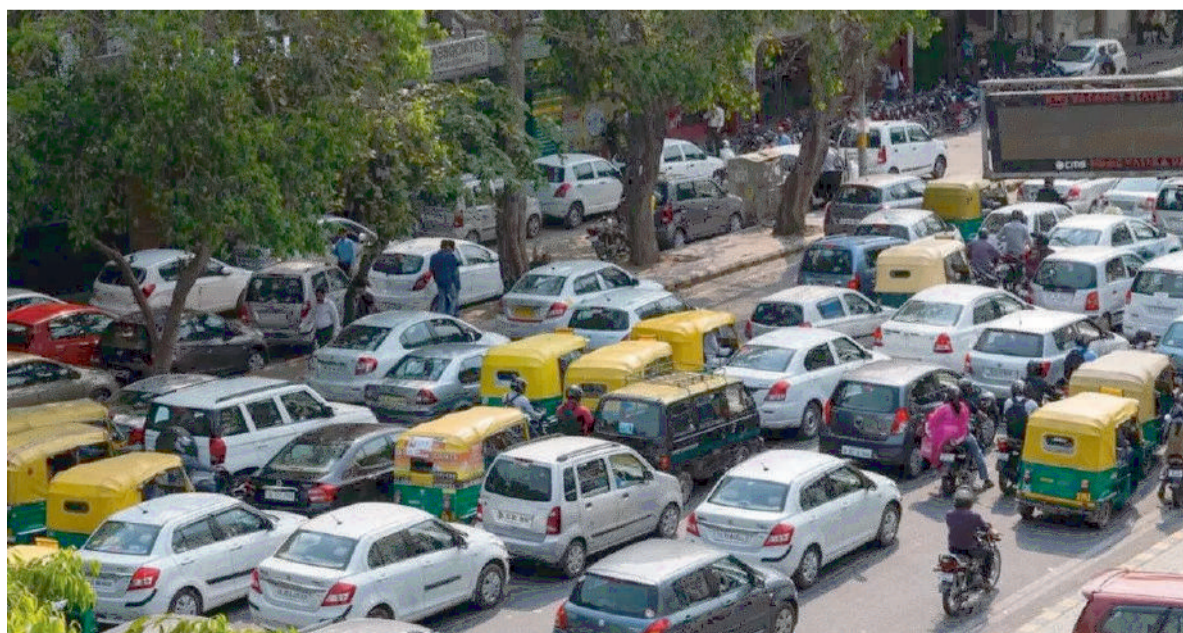
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ग्रेप चार लागू होने पर केवल बीएस-6 मानक वाले वाहनों को ही पेट्रोल और डीजल मिलेगा। इस कदम से प्रदूषण पर काबू पाने में मदद मिलेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सभी पेट्रोल पंप मालिकों को पत्र भेजकर सहयोग करने का अनुरोध किया है।

नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली पुलिस को ट्रैफिक यूनिट ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दिल्ली में ग्रेप चार (ग्रेड्ड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) लागू हो जाने पर केवल बीएस-6 मानक वाले वाहनों (BS6 Vehicles) को ही पेट्रोल और डीजल मिलेगा।

यानी पेट्रोल-डीजल केवल उन वाहनों को मिलेगा जो नए बीएस-6 मानकों को पूरा करते हैं। इस कदम से प्रदूषण पर काबू पाने में कुछ हद तक सफलता मिलने की उम्मीद है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सभी पेट्रोल पंप मालिकों को पत्र भेजकर अनुरोध किया है कि वे बीएस-6 वाहनों के अलावा किसी अन्य वाहन को पेट्रोल या डीजल न दें।

प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को किया जाएगा जप्त

ग्रेप चार लागू होते ही दिल्ली पुलिस फिर पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। सोमवार रात 12 बजे से ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने प्रदूषण कम करने के लिए ज़रूरी कदम उठाना शुरू कर दिया था। पिछली बार की तरह इस बार भी प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होने



वाले वाहनों का चालान किया जाएगा और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को जप्त किया जाएगा।

पिछले ग्रेप-4 के दौरान करीब 350 वाहनों का हुआ था चालान

पिछले ग्रेप-4 (GRAP-4) के दौरान करीब 350 ऐसे वाहनों का चालान किया गया था जोकि बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के चल रहे थे। वहीं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी

कैमरों से नजर रखेगी ताकि आदेश का पालन किया जा सके।

वहीं दूसरी ओर राजधानी में वायु प्रदूषण की गंभीर होती स्थिति के चलते इस साल दूसरी बार ग्रेप चार को लागू करना पड़ा है, लेकिन नियमों के पालन के लिए बनी टीम केवल खानापूरी करती हुई नजर आ रही है।

बीएस-4 वाहनों का धड़ल्ले से हो रहा

दिल्ली में प्रवेश

दिल्ली में सड़क से उड़ती हुई धूल को रोकने के लिए प्रशासन सक्रिय नहीं दिख रहा है और न ही प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार बीएस-4 के वाहनों का प्रवेश को रोक पा रहा है। टोल के बड़े नाकों पर दिल्ली में प्रवेश के लिए पुलिसकर्मियों खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन छोटे टोल नाकों के पास मिलीभगत और चोरी-छिपे ट्रकों का प्रवेश हो रहा है।

## धड़ल्ले से घुस रहे हैं दिल्ली में ट्रक, नहीं किया जा रहा ग्रेप के नियमों का पालन

दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है लेकिन नियमों के पालन में लापरवाही देखने को मिल रही है। सड़क से उड़ती धूल बीएस-4 वाहनों का प्रवेश सड़कों के किनारे पड़ा मलबा और लकड़ी जलाकर चलने वाले तंदूर प्रदूषण बढ़ाने के प्रमुख कारण हैं। दिल्ली सरकार की विभिन्न एजेंसियों की संयुक्त टास्क फोर्स भी नियमों के पालन को सुनिश्चित करने में विफल रही है।

नई दिल्ली। राजधानी में वायु प्रदूषण की गंभीर होती स्थिति के चलते इस वर्ष दूसरी बार ग्रेप चार तक को लागू करना पड़ा है, लेकिन नियमों के पालन के लिए बनी टीम केवल खानापूरी करती नजर आ रही है। दिल्ली में न तो सड़क से उड़ती हुई धूल को रोकने के लिए प्रशासन सजग नजर आ रहा है और न ही प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार बीएस-4 के वाहनों का प्रवेश रुक रहा है। टोल के बड़े नाकों पर दिल्ली में प्रवेश के लिए पुलिसकर्मियों खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन छोटे टोल नाकों से मिलीभगत और चोरी-छिपे ट्रकों का प्रवेश हो रहा है। 10 इसी तरह सड़कों के किनारे पड़ा मलबा और खोदाई करके छोड़ी गई सड़कें भी प्रदूषण बढ़ने का कारण हैं। लकड़ी जलाकर चलने वाले तंदूर भी चलते हुए आसानी से दिख जाएंगे। इस वजह से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। यह स्थिति तब है जब दिल्ली सरकार की दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, एमसीडी से लेकर पर्यावरण विभाग और पुलिस की टीम टास्क फोर्स में शामिल है। दैनिक जागरण की टीम ने वायु प्रदूषण के नियंत्रण के जारी नियमों के पालन को लेकर जमीनी पड़ताल की।

यहां पर जगह-जगह नियमों का उल्लंघन पाया गया। सर्वाधिक चिंताजनक प्रतिबंधित वाहनों का प्रवेश होना है। दक्षिणी दिल्ली में फरीदाबाद से एमसीडी के पुलरहालदपुर टोल से ट्रक आसानी से प्रवेश कर रहे हैं। जब टोलकर्मियों से ट्रक के प्रवेश करने पर पूछा गया तो उनका कहना था कि हमसे टोल के लिए मासिक पास ट्रकों ने ले रखा है। इसलिए हम उनको नहीं रोक सकते हैं, वहीं सड़कों पर धूल, लकड़ी के तंदूर जलाने और खोदाई की गई सड़कों के कारण पड़ा मलबा नजर आया।

ग्रेप-4 नियमों की उड़ रही धज्जियां





# प्रत्याशी की जल्द जारी होगी लिस्ट, भाजपा ने घोषित की चुनाव कमेटी, ये नेता हैं शामिल

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी ने 21 सदस्यीय चुनाव समिति का गठन किया है। इस समिति में प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री संगठन महामंत्री विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सभी सातों सांसद शामिल हैं। समिति प्रत्येक सीट पर दो से तीन संभावित उम्मीदवारों के नाम तय करेगी और सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी उम्मीदवारों के चयन के लिए सुझाव ले रही है।



नई दिल्ली। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन के लिए भाजपा ने 21 सदस्यीय चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, संगठन महामंत्री, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, सभी सातों सांसद को शामिल किया गया है। इसी सप्ताह प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें प्रत्येक सीट पर दो से

तीन संभावित प्रत्याशियों की नाम तय किए जाएंगे। इसकी सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी।

कार्यकर्ताओं से सुझाव ले रही भाजपा भाजपा सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों के चयन के लिए कार्यकर्ताओं से सुझाव ले रही है। इसके लिए पार्टी ने सभी 14 संगठनात्मक जिलों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। प्रत्येक पर्यवेक्षक पांच विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। मंगलवार व बुधवार को कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर उनसे क्षेत्र के संभावित प्रत्याशियों के बारे में चर्चा की और लिखित सुझाव लिए।

हर विधानसभा क्षेत्र में कराया सवें इस बार शक्ति केंद्र प्रमुखों को भी प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इनके साथ ही मंडल अध्यक्ष, उस विधानसभा में रहने वाले जिला, प्रदेश व राष्ट्रीय पदाधिकारियों से भी सुझाव लिए जा रहे हैं। अगले एक-दो दिनों में केंद्रीय पर्यवेक्षक दावेदारों की सूची प्रदेश नेतृत्व को सौंप देंगे।

इससे पहले पार्टी ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सवें भी कराया है। सभी सांसदों से भी नाम लिए गए हैं। इन सभी पर प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होगी।

चुनाव समिति के सदस्य प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष महतोत्रा सांसद मनोज तिवारी सांसद योगेंद्र चांदोलिया सांसद कमलजीत सहयवत सांसद रामवीर सिंह बिधुडी सांसद प्रवीण खंडेलवाल सांसद बांसुरी स्वराज पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा प्रदेश संगठन मंत्री पवन राणा महामंत्री विष्णु मित्तल नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष ऋधा पांडेय मिश्रा

चुनाव समिति में प्रदेश चुनाव प्रभारी बैजयंत जय पांडा, चुनाव सह प्रभारी अतुल गर्ग और प्रदेश सह प्रभारी डॉ. अलका गुजर विशेष आमंत्रित सदस्य हैं।

आप विधायकों की मिलीभगत से बन रहे हैं नकली जाति प्रमाण पत्र: सचदेवा वहीं, भाजपा ने आम आदमी पार्टी के विधायकों पर नकली जाति प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज के आधार पर अनुसूचित जाति को मिलने वाला आरक्षण व अन्य लाभ अपात्र लोगों को देने का आरोप लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आशंका है कि रोहिंग्या व बांग्लादेशी घुसपैठियों के नकली दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। उन्होंने उपराज्यपाल से इसकी सीबीआई जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की।

## एसिड हमले का पीड़ित किसी भी राज्य से हो, फंड का जरूर मिलेगा लाभ: दिल्ली HC ने की अहम टिप्पणी



परिवहन विशेष न्यूज

एसिड अटैक पीड़िता दिल्ली हाईकोर्ट ने एसिड हमले के पीड़ितों के लिए अवलंबन फंड योजना- 2024 को लागू करने का आदेश दिया है। इस योजना का लाभ पीड़ित को दिया जाएगा भले ही वह राष्ट्रीय राजधानी के निवासी हों या नहीं। योजना में पुनर्वास और अन्य सहायक खर्चों को पूरा करने के लिए 10 करोड़ रुपये का स्थायी कोष होगा।

नई दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद एसिड हमले के पीड़ितों के लिए अवलंबन फंड योजना-2024 को लागू करने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस योजना का लाभ पीड़ित को दिया जाएगा भले ही वह राष्ट्रीय राजधानी के निवासी हों या नहीं या फिर उनका पता कुछ भी हो।

मुख्य न्यायाधीश मनमोहन (अब सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत) और न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा तैयार की गई इस योजना में पुनर्वास और अन्य सहायक खर्चों को पूरा करने के लिए 10 करोड़ रुपये का स्थायी कोष होगा। एसिड हमले के पीड़ितों और इसका संचालन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) द्वारा किया जाएगा।

अदालत ने कहा कि निर्देशित किया जाता है कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) योजना के कार्यान्वयन के लिए एक अलग खाता खोलेंगे और इसके बाद इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल एएसआरएफ फंड में पड़ी धनराशि को अवलंबन फंड योजना-2024 (Avalamban Fund Scheme) के तहत नए खोले गए खाते में स्थानांतरित करेंगे।

पीठ ने कहा कि इस न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के आदेशों के तहत लगाया गया जुर्माना और लागत योजना के तहत जमा करने का निर्देश भी निधि के कोष में जोड़ा जाएगा। मूल रूप से यह मामला पोक्सो मामले में आरोपित की जमानत याचिका से जुड़ा है और मूल याचिका का एकल पीठ ने निपटारा कर दिया था।

लेकिन, यह आरोप लगने के बाद मामला दो सदस्यीय पीठ के समक्ष रखा गया था कि दुष्कर्म के साथ-साथ नाबालिग पीड़िता को जबरन टॉयलेट क्लीनर भी पिलाया गया था। इस पर पीठ ने कहा कि ऐसे में जब दुनिया में साहस को क्रूरता से मुकाबला करना है, तो उन पीड़ितों के दिल को दहला देने वाले ऐसे जख्म कराने के लिए एक योजना तैयार करना जरूरी है।

अदालत ने कहा कि ऐसी घटनाओं को झेलने वाली पीड़िता ने केवल शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चोटों का सामना करती हैं, बल्कि अकल्पनीय दर्द, पीड़ा और आतंक को भी सहन करती हैं। पीठ ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-396 पीड़ित मुआवजा योजना स्थापित करने और इसके लिए धन उपलब्ध कराने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों की जिम्मेदारियों को रेखांकित करती है।

इसमें कहा गया है कि दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना-2018 के तहत पीड़ितों की क्षतिपूर्ति आवश्यकताओं को विधिवत मान्यता दी गई है और इनका निवारण किया जाएगा।

ये होंगे नोडल अधिकारी योजना को लागू कराने के लिए प्रत्येक अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। साथ ही फंड की निगरानी के लिए प्रधान जिला एवं सत्र

न्यायाधीश (मुख्यालय) दिल्ली उच्च न्यायिक के एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी को नोडल अधिकारी के तौर पर नामित कर सकते हैं।

ये पीड़ित ले सकेंगे योजना का लाभ

ऐसा व्यक्ति जिस पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एसिड हमला हुआ हो या फिर वह दिल्ली का निवासी हो या फिर इस संबंध में किसी भी अस्पताल में उसका इलाज हो चुका है।

ऐसे मिलेंगे वित्तीय सहायता

वित्तीय सहायता लेने के लिए दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण अपनी परियोजना "संपर्क" के तहत दुष्कर्म, एसिड हमले सहित महिलाओं के खिलाफ सभी अपराधों की एफआईआर की प्रति प्राप्त करेगा। विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता एवं सहायता कार्यवाही होगी।

एसिड अटैक की एफआईआर मिलते ही तुरंत कानूनी सहायता के लिए वकील नियुक्त किया जाएगा। पीड़ित को अवलंबन फंड योजना और इसके बारे में अवगत कराया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए पीड़ित को स्वयं आवेदन करना होगा।

फंड अकाउंट का होगा ऑडिट

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नोडल अधिकारी (मुख्यालय) योजना से संबंधित खातों का रखरखाव करवाएंगे। योजना से संबंधित खातों का ऑडिट जिला न्यायालयों में उक्त प्रयोजन हेतु नियमों के तहत किया जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) योजना के तहत उपयोग की गई धनराशि के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को अर्धवार्षिक रिपोर्ट पेश करेंगे।

## ग्रेटर नोएडा नहीं अब दिल्ली में यहां है देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स, उपराज्यपाल ने किया उद्घाटन

परिवहन विशेष न्यूज

भारत में सबसे लंबा गोल्फ कोर्स दिल्ली के द्वारका में देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स बनकर तैयार हो गया है। उपराज्यपाल सक्सेना ने बुधवार को इस गोल्फ कोर्स का उद्घाटन किया। यह गोल्फ कोर्स अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस है और इसमें न सिर्फ देश बल्कि विदेश के गोल्फ प्रेमियों को आकर्षित करने की पूरी क्षमता है। गोल्फ कोर्स के निर्माण पर करीब 250 करोड़ की लागत निर्धारित है।

नई दिल्ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बुधवार को देश के सबसे लंबे गोल्फ कोर्स (अभी तक ग्रेटर नोएडा का जेपी ग्रीस गोल्फ कोर्स सबसे लंबा 7347 यार्ड था) का उद्घाटन उपनगरी द्वारका में किया। सेक्टर 24 स्थित इस गोल्फ के बनने से दिल्ली एनसीआर के गोल्फ प्रेमियों को विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त एक और गोल्फ कोर्स की सुविधा मिलेगी। उद्घाटन के अवसर पर पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत व दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधुडी, डीडीए उपाध्यक्ष विजय कुमार सिंह भी मौजूद रहे। उपराज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि यह गोल्फ कोर्स अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा से लैस है। इस गोल्फ कोर्स में न सिर्फ देश बल्कि विदेश के गोल्फ प्रेमियों को आकर्षित करने की पूरी क्षमता है। यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही गुरुग्राम में लोग

जापान से चार्टर विमान पर सवार होकर गोल्फ खेलने आते हैं।

पीएम ने देश में खेलों को बढ़ावा देने में निभाई अग्रणी भूमिका-एलजी

ऐसे लोग भविष्य में यहां भी आएंगे। यहां गोल्फ से जुड़े राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय आयोजन भविष्य में होंगे। खेल हदमारी जीवनशैली को समृद्ध बताते हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में खेलों को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाई है। वर्ष 2019 में, उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की, जिसने खेलों को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने में काफी मदद की है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में हमारे खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन इस अभियान की सफलता को दर्शाता है। आने वाले समय में यहां गोल्फ अकादमी व गोल्फ क्लब की सुविधा मिलेगी। गोल्फ क्लब में पंचसितारा होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। उपराज्यपाल ने कहा कि दोनों के निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया चल रही है।

गोल्फ कोर्स की विशेषता देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स, जिसकी कुल लंबाई 7377 यार्ड यानि 6.7 किलोमीटर है।

कुल होल- 18 कुल बे- 52 कुल कैपिलरी बंकर-63 कुल क्षेत्रफल- 158 एकड़ कार्ट पाथ की कुल लंबाई- सात किलोमीटर



ये है देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स

सिंचाई के लिए कंप्यूटर से जुड़ी स्वचालित प्रणाली, कुल 1550 स्प्रिंकलर लगे हैं।

चार झील हरित क्षेत्र में नार्थ शोर एस्पल्टी बरमूडा घास का इस्तेमाल देश के किसी भी गोल्फ कोर्स में यहां पहली बार हुआ है। इस घास का रंग, खारा पानी, अत्यधिक गर्मी व सूखा के प्रति इसकी सहनशीलता, सीधा क्षेत्रीय सघन विकास इस घास को विशेष बनाता है।

वर्ष 2019 में रखी गई थी आधारशिला द्वारका में गोल्फ कोर्स की योजना करीब दो दशक पुरानी है। लेकिन कभी बजट का अभाव तो कभी जमीन से जुड़ी अड़चनों को दूर करने के बाद इस गोल्फ कोर्स के निर्माण की आधारशिला वर्ष 2019 में रखी गई थी। आधारशिला रखे जाने के बाद तेजी से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन बाद में कोरोना महामारी के कारण इसका निर्माण विलंबित होता चला गया।

गोल्फ कोर्स के निर्माण पर करीब 250 करोड़ की लागत निर्धारित है। अभी गोल्फ कोर्स के निर्माण के दो और चरण शेष हैं। इसमें क्लब हाउस व गोल्फ अकादमी शामिल हैं। अभी यहां एक बार में एक टूर्नामेंट कराया जा सकता है। अभी यहां एक बार में 26 प्लेटफॉर्म से 52 खिलाड़ियों के खेलने की सुविधा है। फिलहाल यहां सदस्यता दिए जाने की शुरुआत कर दी गई है।

डीडीए का अपना तीसरा गोल्फ कोर्स अभी दिल्ली में डीडीए (DDA) के अधीन दो गोल्फ कोर्स कुतुब गोल्फ कोर्स (Qutub Golf Course) व भलस्वा गोल्फ कोर्स (Bhalswa Golf Course) हैं। इसके अलावा दिल्ली में डॉ जाकिर हुसैन मार्ग पर दिल्ली गोल्फ कोर्स हैं। छावला में भी सीमा सुरक्षा बल परिसर में एक गोल्फ कोर्स है। धौलाकुआं में भी दिल्ली छावनी इलाके में एक गोल्फ कोर्स है। द्वारका सेक्टर 24 का गोल्फ कोर्स डीडीए का तीसरा गोल्फ कोर्स है।

## दिल्ली में 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का होगा मुफ्त इलाज, केजरीवाल ने किया 'संजीवनी योजना' का एलान...

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना शुरू करने का एलान किया है। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी दिल्लीवासियों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार उनके इलाज का पूरा खर्च उठाएगी। इस योजना के शुरू होने पर दिल्ली के लाखों बुजुर्गों को लाभ होगा।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना शुरू करने का एलान किया है। इस योजना के तहत दिल्ली में 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों का निःशुल्क उपचार दिया जाएगा। केजरीवाल ने एलान किया कि उनके उपचार का पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी।

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बुजुर्गों के उपचार के लिए संजीवनी योजना लागू करने का वादा किया है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की। केजरीवाल ने कहा, इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों का दिल्ली में निःशुल्क उपचार होगा। चुनाव के बाद सरकार बनने के बाद इसे लागू किया जाएगा।

तीर्थ यात्रा का पूरा खर्च उठाती है सरकार उन्होंने कहा, श्रवण कुमार से प्रेरित होकर उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली के लाभग एक लाख बुजुर्ग देश के कोने-कोने में स्थित तीर्थ स्थलों की यात्रा कर चुके हैं। तीर्थ यात्रा का पूरा खर्च सरकार उठाती है।

इसके बदले हम सभी को दुआ मिलती है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। इस उम्र में सभी को अपने स्वास्थ्य की चिंता होती है। उम्र बढ़ने के साथ ही कई तरह की बीमारियों से व्यक्ति पीड़ित हो जाता है। उसके लिए उपचार करना सबसे बड़ी



चिंता होती है।

चिंता की कोई बात नहीं अर्थिक रूप से संपन्न कई परिवारों में भी बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखा जाता है। लेकिन, चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि उनका यह बेटा अभी जीवित है। रामायण में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी लेकर आए थे। भेदभाव या कोई शर्त नहीं होगी केजरीवाल ने कहा आम आदमी पार्टी दिल्ली में बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना शुरू करेगी। 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को इसका लाभ मिलेगा। इसमें किसी तरह का भेदभाव या कोई शर्त नहीं होगा। प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को यह सुविधा मिलेगी। उपचार में खर्च की भी कोई सीमा नहीं होगी। उपचार सरकारी अस्पताल में हो या

निजी अस्पताल में पूरा खर्च सरकार उठाएगी।

चुनाव से पहले शुरू कर दिया जाएगा पंजीकरण

योजना चुनाव के बाद लागू होगी, लेकिन पंजीकरण शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए बुजुर्गों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर-घर जाकर बुजुर्गों का पंजीकरण कर उन्हें काई देंगे।

महिलाओं के लिए भी किया था बड़ा एलान

इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सभी महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की थी। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव के बाद दिल्ली की हर महिला के खाते में 2100 रुपये भेजे जाएंगे।

## 'दिल्ली में आप विधायक बनवा रहे फर्जी दस्तावेज', अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण पर क्या बोले वीरेंद्र सचदेवा?

दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी (AAP) पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि दिल्ली में आप विधायकों द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण का लाभ भी दूसरों को दिया जा रहा है। पढ़िए-उन्होंने आप को लेकर और क्या-क्या कहा है।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आम आदमी पार्टी की सरकार व विधायकों पर नकली जाति प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज के आधार अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण का लाभ गैर पात्र लोगों को देने का आरोप लगाया है।

आप विधायकों की मिलीभगत से तैयार किए जा रहे नकली दस्तावेज

दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि द्वारका जिले में आप विधायकों की मिलीभगत से नकली दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। आशंका है कि नकली दस्तावेज रोहिंग्या व बांग्लादेशी घुसपैठियों के बनाए जा रहे हैं। उन्होंने उपराज्यपाल से इसकी सीबीआई जांच कराने और दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। दिल्ली की आप सरकार इसमें विफल रही है। नकली दस्तावेज के माध्यम से दूसरे लोगों को यह लाभ दिया जा रहा है।

नौकरी में आरक्षण, बच्चों की शिक्षा में मिलती है छूट

उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य सरकारी दस्तावेज के आधार पर अनुसूचित जाति के लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ देना प्रत्येक सरकार का दायित्व है। दिल्ली की आप सरकार इसमें विफल रही है। नकली दस्तावेज के माध्यम से दूसरे लोगों को यह लाभ दिया जा रहा है।

वंचितों को उनके अधिकार से रखा जा रहा वंचित

सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में आप विधायकों



प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा, अनुसूचित जाति के लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ देना प्रत्येक सरकार का दायित्व है। दिल्ली की आप सरकार इसमें विफल रही है। नकली दस्तावेज के माध्यम से दूसरे लोगों को यह लाभ दिया जा रहा है।

की मिलीभगत से नकली आधार कार्ड व जाति प्रमाण पत्र बनाकर अनुसूचित जाति के लोगों को उनके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है।

द्वारका में इस तरह के आठ मामले पकड़े भाजपा कार्यकर्ताओं ने द्वारका में इस तरह के आठ मामले पकड़े हैं। पूरी दिल्ली में इस तरह के कई मामले हो सकते हैं। आप विधायकों के कार्यालय में आधार कार्ड बनाने की व्यवस्था की गई थी।

आप विधायकों के यहां से हटाई गई आधार कार्ड बनाने की मशीन

बताया कि लोकसभा चुनाव के समय इसकी जानकारी मिलने पर अधिकारियों से शिकायत की गई थी। उसके बाद आप विधायकों के यहां से आधार कार्ड बनाने की मशीन हटाई गई थी, लेकिन वहां बने नकली आधार कार्ड की जांच नहीं हुई है। अधिकवक्ता सत्य रंजन ने कहा, यह अपराध है। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे को घेरने में लगे हुए हैं। कभी बीजेपी आप पर कोई बड़ा आरोप लगाती है तो कभी आप भाजपा को कानून व्यवस्था पर घेरती नजर आती है।

# हो जाएं सावधान! अगर ऐसे ले ली सेल्फी तो आपका बैंक खाता हो जाएगा खाली

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा पुलिस साइबर अपराधसाइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक रहे। नोएडा के सेक्टर-47 स्थित जागरण पब्लिक स्कूल में साइबर एक्सपर्ट रवि प्रजापति और विकास ढाका ने छात्र-छात्राओं को कई चौकाने वाले तथ्य बताए। उन्होंने छात्राओं को ठगी समेत किसी भी तरह के अपराध से बचने के लिए विशेष टिप्स दिए। आप भी इस खबर के माध्यम से जरूरी टिप्स पढ़ें।

**नोएडा।** भागदौड़ भरी जिंदगी में मुश्किल से मुश्किल काम को मेहनत, लगन और ईमानदारी से जीतने में अलग ही खुशी मिलती है। वचुअल वर्ल्ड ने खुशी के पल को इंटरनेट मीडिया पर जिस तरह किसी भी व्यक्ति तक पहुंचाने की जो सुविधा दी है, उसे गिरोह ने साइबर ठगी के लिए हथियार बना लिया है।

बुधवार को साइबर एक्सपर्ट रवि प्रजापति और विकास ढाका ने सेक्टर-47 स्थित जागरण पब्लिक स्कूल में दैनिक जागरण द्वारा चलाए जा रहे "लुटेरा ऑनलाइन" जागरूकता अभियान में छात्र-छात्राओं को कई चौकाने वाले तथ्य बताए। उन्होंने छात्राओं को ठगी समेत किसी भी तरह के अपराध से बचने के लिए विशेष टिप्स दिए।

**टेफकॉम बताएगा आपके नाम पर हैं कितने मोबाइल नंबर**  
साइबर एक्सपर्ट रवि प्रजापति ने बताया कि हर

व्यक्ति अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। ज्यादातर लोग सड़क किनारे अनजान व्यक्ति को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या महत्वपूर्ण दस्तावेज दे देते हैं। वहां नए उपभोक्ता से एक बार में अंगूठे के निशान न आने पर दोबारा प्रक्रिया कराई जाती है।

इसी बहाने से शांतिर उपभोक्ताओं के नाम पर कई सिम निकालकर गिरोह को बेच देते हैं। फिर उस सिम का ठगी के लिए प्रयोग होता है। गौतमबुद्धनगर पुलिस उपभोक्ताओं का डाटा बेचने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर चुकी है।

एक्सपर्ट ने छात्र-छात्राओं को बताया कि कोई भी व्यक्ति अब आसानी से पता कर सकता है कि उनके कागजात पर कितनी सिम चल रही हैं। केंद्र सरकार ने टेफकॉप नाम से पोर्टल बनाया हुआ है। कोई भी वेबसाइट पर पोर्टल खोलकर उसमें अपना मोबाइल नंबर डालकर प्रक्रिया पूरी करते ही तथ्य पता कर सकता है।

**खुशी वाले विक्टरी साइन से ऐसे ठगते हैं अंगूठे-अंगुलियों के निशान**  
साइबर एक्सपर्ट विकास ढाका ने छात्राओं को बताया कि हम छोटी-छोटी खुशी के पल को विक्टरी वाले साइन के साथ इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। साइबर ठग उसी विक्टरी साइन से अंगुलियों के निशान लेकर ऑनलाइन डाटा निकाल लेते हैं। 2020 में गौतमबुद्धनगर पुलिस ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश कर चुकी है।

साइबर ठग अब छात्राओं के इंटरनेट मीडिया अकाउंट खोलकर उन्हें ब्लैकमेल करके या फिर

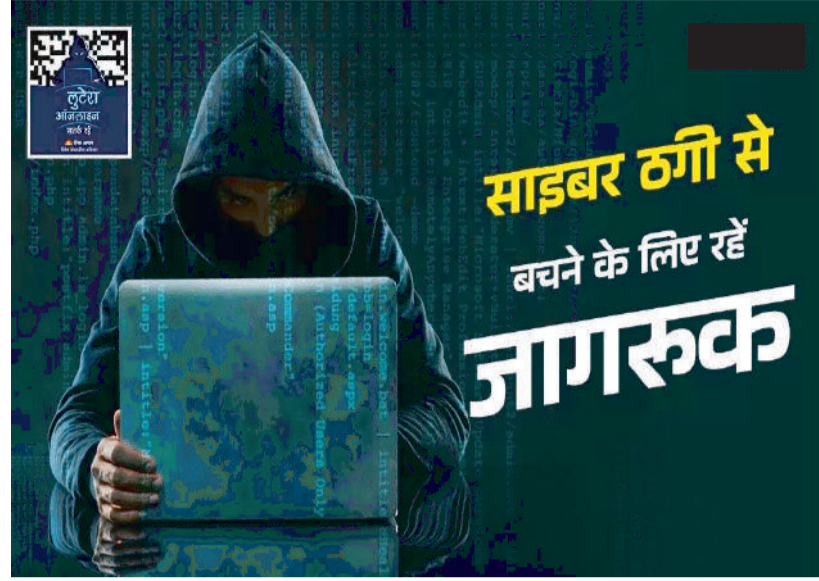
अश्लील वीडियो चैट से बदनाम करने की धमकी देते हैं। उन्होंने सभी से अपने अकाउंट में स्टेप-टू-वेरिफिकेशन प्रक्रिया आन करने और इंटरनेट मीडिया पर अनजान लोगों से दूरी बनाने की अपील की।

**यह बनें साइबर योद्धा**  
साइबर एक्सपर्ट ने बताया कि सेल्फी से भी ठगी हो जाती है। यह मेरे लिए नई जानकारी है। इंटरनेट मीडिया के जरिए विदेशों में बैठे लोग आसानी से ठगी कर लेते हैं। यह काफी चौकाने वाली बात है। दैनिक जागरण ने अच्छा अभियान चलाया हुआ है। वह इससे जुड़ गई हैं। **सान्या-छात्रा**

पुलिस या कोई अधिकारी वीडियो करके गिरफ्तार नहीं करता है। मैं पहले पुलिस से थोड़ा घबराती थी। अब दैनिक जागरण के अभियान से काफी आत्मविश्वास बढ़ गया है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। इससे बचने के लिए मैं और लोगों को जागरूक करूंगी। **साक्षी-छात्रा**

कई बार छात्राएं छोटी-छोटी घटनाओं की शिकायत नहीं करती हैं। फिर उसके गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी साइबर ठगों के खिलाफ जागरूक करने की है। मैं इस अभियान का हिस्सा बनना चाहूंगी। **तनिष्का चौहान-छात्रा**

साइबर अवेयरनेस की क्लास में बताया कि फेसबुक और सभी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर फोटो एडिट करके ब्लैकमेल किया जाता है। यह मेरे लिए नई जानकारी है। दैनिक जागरण ने मुझे नई



साइबर ठगी से बचने के लिए रहें जागरूक

जानकारी दिलाई है। मैं इसे हमेशा ध्यान रखूंगी औरों को बताऊंगी। **आकृति अग्रवाल, छात्रा**  
साइबर अभियान से पता चला कि हम कोई भी अपराध की शिकायत आनलाइन एनसीआरबी या यूपीकाप पर कर सकते हैं। महिला संबंधी अपराध में गोपनीयता भी बनी रहती है। मुझे पहले इसकी जानकारी नहीं थी। मुझे क्लास में काफी सारी जानकारी मिली है। अब मैं अपने घर और आसपास लोगों को भी बता सकूंगी। **आकांक्षा तिवारी-**

**छात्रा**  
वचुअल वर्ल्ड ने लोगों को सावधानी के साथ नई-चुर्नीतियों से भी सामना करना सिखा दिया है। आंकड़ों से पता चला कि हर दूसरा व्यक्ति साइबर ठगों के निशान पर है। यह काफी गंभीर का विषय है। दैनिक जागरण को ऐसे अभियान समय-समय पर कराने चाहिए। इससे जागरूकता बढ़ेगी और लोगों की जमापूंजी बचेगी। **ऋषभ शर्मा-सेक्टर-99 नोएडा**

## नौ दिन बाद ऐसे खुला राज, चार माह की मासूम सकुशल बरामद; पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा

अर्चना को गोद में किस्मत के आते ही उसका चेहरा खिल उठा। चार माह की बच्ची भी मां की गोद में आकर खिलखिलाने लगी। जी हां नौ दिसंबर को रेलवे स्टेशन से चार माह की बच्ची का अपहरण करने वाले विकास को बुधवार को जीआरपी की टीम ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से गिरफ्तार कर लिया है। जानें पूरी खबर।



**गाजियाबाद।** नौ दिसंबर को रेलवे स्टेशन से चार माह की बच्ची का अपहरण करने वाले विकास को बुधवार को जीआरपी की टीम ने पीलीभीत से गिरफ्तार कर लिया है।

सीओ जीआरपी सुदेश गुप्ता ने बताया कि बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया है। मंगलवार देर रात को अपहरणकर्ता को पीलीभीत से 45 किलोमीटर दूर बहन के घर से पकड़ा गया है।

इस केस का पर्दाफाश करने के लिए जीआरपी की टीम ने नौ दिन में दिल्ली, पानीपत और सोनीपत के सात सीसीटीवी खंगाले। सही सुराग पानीपत रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगालने पर लगा। यहां से पूछताछ करके पता चला कि आरोपित पीलीभीत का रहने वाले है।

**घटना के बाद आरोपित घूमता रहा**  
प्रभारी निरीक्षक जीआरपी अनुज मलिक ने बताया कि अपहरण के दिन जिस मोबाइल फोन का उपयोग कर रहा था, उसे ट्रेस करने पर पता चला कि वह मोबाइल उसने पानीपत से एक व्यक्ति से चुराया था। घटना के बाद आरोपित दिल्ली और पानीपत में ही घूमता रहा।

एक टीम दिल्ली और एक पानीपत में लगातार उसकी निगरानी को तैनात रही। प्रारंभिक जांच में पता चल गया था कि आरोपित का नाम विकास है। नौ दिसंबर को रेलवे स्टेशन से दीपक की चार माह

की बेटी को विकास अपहरण करके ले गया था। दीपक ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्त को फोटो दिखाकर लोगों से कई दिन तक पूछताछ की गई है। आसपास के सीसीटीवी की फुटेज खंगाली गई लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दिल्ली और पानीपत में टीम की सक्रियता उसका पता चला कि बच्ची को लेकर वह पीलीभीत स्थित अपनी बहन के घर चला गया है।

**कोहरे के चलते कई ट्रेन देर से चलीं**  
सर्दी बढ़ने और कोहरा के चलते बुधवार को भी कई लोकल और एक्सप्रेस ट्रेन देरी से चलीं। अधिकारियों के अनुसार कोई दो तो कोई ट्रेन तीन घंटे देरी से रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इसके चलते यात्री सर्दी में रेलवे स्टेशन पर खुलने में बैठकर इंतजार करने को मजबूर हो रहे हैं।

रेलवे द्वारा कोहरे के चलते 28 फरवरी तक के लिए कई लोकल और एक्सप्रेस गाड़ियों का संचालन अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया है। इनमें गाजियाबाद में ठहरकर चलने वाली 16 ट्रेनें शामिल हैं।

ट्रेनों के देरी से चलने से प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। इसके लिए आरपीएफ और जीआरपी ने सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी है।

## किशोरी को किडनैप करके ले गया युवक, रास्ते में घटी ये घटना; पुलिस और लड़की के परिजन आमने-सामने

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद क्राइम न्यूज गाजियाबाद के अबुपुर में एक किशोरी की मौत के मामले में पुलिस और परिजनों के बीच विवाद है। पुलिस इसे सड़क हादसा बता रही है जबकि परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। किशोरी के पिता का कहना है कि उनकी बेटी को एक युवक अगवा कर ले गया था और रास्ते में उसकी हत्या कर दी।

**गाजियाबाद।** दिल्ली मेट्रॉ मार्ग पर अबुपुर के निकट किशोरी की मौत की घटना को निवाड़ी पुलिस हादसा बता रही है, जबकि स्वजन इसे हत्या बता रहे हैं। किशोरी को एक युवक अगवा कर ले जा रहा था। रास्ते में लड़की की मौत हो गई।

किशोरी के पिता का आरोप है कि ईंट से वार कर किशोरी की हत्या की गई, जिसके बाद शव को सड़क पर फेंका गया। किशोरी को आरोपी 16 दिसंबर को अपने साथ लेकर गया था। देर रात उन्हें किशोरी की मौत के बारे में पता चला।

**पुलिस ने बताया सड़क हादसा**  
पुलिस ने सड़क हादसे में मौत का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का दावा है कि सड़क पर खून मिला है। आरोपी का भी अस्पताल में उपचार चल रहा है।

**बाइक से जबरन ले जाने का आरोप**  
पुलिस के अनुसार, एक कॉलोनी की किशोरी 16 दिसंबर को घर से निकली थी। आरोप है कि रास्ते में एक आरोपी ने उसे जबरन बाइक पर बैठा लिया। आरोपी उसे



जबरन अपने साथ ले जाने लगा। पीछे दूसरा युवक बैठा था। आरोपी युवक दूसरे समुदाय से जुड़ा है। किशोरी का रात तक भी पता नहीं चला तो स्वजन ने आसपास पता किया।

**शव मिलने का चला पता**  
उन्हें जानकारी हुई कि किशोरी का शव अबुपुर के निकट मिला है। किशोरी के सिर में चोट का गंभीर घाव है। स्वजन का आरोप है कि आरोपी युवक ने पहले भी किशोरी को थपड़ मारे थे। वह किशोरी से खफा था।

इसलिए खुन्नस रखता था। ऐसे में प्रकरण की गंभीरता से जांच होनी जरूरी है। **किशोरी के जीजा ने दर्ज कराया केस**

एसीपी मोदीनगर का कहना है कि मामले में किशोरी के जीजा की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। छानबीन की जा रही है। शुरूआती जांच में सड़क हादसे में ही मौत की बात पट्टे हुई है। फिलहाल हत्या का कोई साक्ष्य सामने नहीं आया है।

**सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर दो लाख की ठगी**  
वहीं, मुरादनगर थाना क्षेत्र की राधेश्याम विहार कॉलोनी में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर एक व्यक्ति के साथ दो लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया

है। नगर की राधेश्याम विहार कॉलोनी में रहने वाले अनुज शर्मा सरकारी सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं। अनुज के अनुसार एक वर्ष पूर्व कोचिंग वह एक व्यक्ति से मिले थे। उक्त व्यक्ति ने युवक को आशवासन दिया था कि वह उनकी नौकरी दिल्ली के जलकल विभाग में लगवा देगा, लेकिन इसके लिए उनको पांच लाख रुपये बतौर सुविधा शुल्क देने होंगे। सरकारी नौकरी के झांसे में आकर युवक ने आरोपित को दो बार में एक लाख रुपये दे दिए। बाकी रकम नौकरी लगाने के बाद देनी थी।

## शाबाश ऑफिसर!-ऑफिस में बुजुर्ग शख्स को इंतजार करवाया -बॉस ने स्टाफ को दी अनोखी सजा - मरते दम तक याद रखेंगे

गोंदिया - वैश्विक स्तर पर भारत को बौद्धिक क्षमता का धनी माना जाता है, परंतु भ्रष्टाचार स्वार्थ मलाई कामचोरी व जनता को चकरे खिलाने में माहिर करीब सभी कार्यालयों के अनेकों कर्मचारी अपनी बौद्धिक क्षमता का गलत इस्तेमाल अपने, निजी आरामदायक सुविधाओं के लिए चंद्र रूप्यों के लिए आम जनता, विशेष रूप से बुजुर्गों को भी अपनी टेबल के चकरे खिलाने में माहिर होते हैं, जो देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, इसका अनुभव मैंने स्वयंभू में भी अनेकों शासकीय कार्यालय में चकरे खाकर महसूस किया है कि करीब करीब हर अधिकारी चकरे खिलाने में माहिर होता है। हमारा पीएम या पूरा मंत्रिमंडल चाहे कितनी भी बातें भ्रष्टाचार के खिलाफ कर लें परंतु जमीनी स्तर पर असर अभी भी कम नहीं हो रहा है। चंद्र रूप्यों याने चाय पानी के लिए टेबल के 10 चकरे खाना ही पड़ता है या फिर मजबूरी से किसी दलाल के थू काम करना पड़ता है जो अत्यंत ही चिंताजनक है, जो हमारे पीएम के सपनों को चकनाचूर करने में लगे हुए हैं। इसलिए इस आर्टिकल के माध्यम से मैं 20 दिसंबर 2024 तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में एक विधेयक अधिसूचित करने का सुझाव देता हूँ जो सीधा ऑफिस के टेबलों के चकरे खिलाने वाले बाबुओं कर्मचारियों और अधिकारियों अधीक्षकों व सीईओ को द्वारा सीसीटीवी कैमरे में देखकर भी कुछ एक्शन नहीं लेकर मूक दर्शक बने रहते हैं उनके खिलाफ भी सीधे केस दर्ज करवा कर निलंबित करने का प्रावधान संसद में माहिर आचार संहिता की धाराओं को शामिल कर विधेयक को यदि इस शीत सत्र में पेश करना संभव नहीं हो तो, पूरी तैयारी के साथ अगले वर्ष 2025 के बजट सत्र में पेश किए जाने की संसद जरूरत है। आज हम इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिनांक 17 दिसंबर 2024 को पूरे सोशल मीडिया में एक विलप बहुत ही तीव्र गति से संकुलित हो रही है जिसमें बुजुर्गों को फाइल क्लियर कराने के लिए

एक ऑफिस में चकरे काटने पड़ रहे हैं, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है इतना तक कि अधीक्षक या सीईओ या बॉस ने सीसीटीवी में देखकर संबंधित कर्मचारियों को हिदायत देने के बावजूद उस बुजुर्ग का काम नहीं हुआ तो बॉस ने पूरे स्टाफ को एक अनोखी सजा दी, जिसका संज्ञान पूरे भारत के शासकीय व निजी अधिकारियों या बॉस ने लेना समय की मांग है। इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से व उपलब्ध हमें का प्रयोग करके इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, सरकारी कार्यालयों में छोटे-छोटे कामों के लिए कर्मचारियों द्वारा जनता को चकरे लगवाने वाले कर्मचारियों के लिए सजा का अध्यादेश लाना जरूरी है।

साथियों बात अगर हम सोशल मीडिया में 17 दिसंबर 2024 शाम से वायरल एक क्लिप की करें तो, दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा से अनोखा मामला सामने आया है। वहां के सीईओ ने कर्मचारियों की लापरवाही पर कड़ा एक्शन लेते हुए आवासीय भूखंड विभाग के स्टाफ को आधे घंटे तक खड़े होकर काम करने का फरमान सुना दिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वह चैनलों के अनुसार के अनुसार एक बुजुर्ग दंपती अपनी समस्या के समाधान के लिए प्राधिकरण के आवासीय भूखंड विभाग पहुंचे थे, लेकिन घंटों इंतजार के बावजूद उनका काम नहीं हो सका, जिसके बाद सीईओ ने कर्मचारियों को ये सजा सुनाई। दरअसल, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने अपने ऑफिस में दंपती की सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन पर बुजुर्ग दंपती को काफी देर तक खड़े देखा तो तुरंत आवासीय भूखंड विभाग को निर्देश दिया कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन उसके बावजूद 15-20 मिनट बाद जब सीईओ ने फिर से सीसीटीवी पर नजर डाली तो बुजुर्ग दंपति तब भी खड़े दिखे, इस पर नाराज सीईओ आवासीय विभाग पहुंचे और कर्मचारियों की लापरवाही पर कड़ी फटकार लगाई। सीईओ ने कर्मचारियों को कहा, जब आप

खड़े होकर काम करेंगे तभी बुजुर्गों की परेशानी को समझ पाएंगे। इसके बाद उन्होंने सभी कर्मचारियों को आधे घंटे तक खड़े होकर काम करने का निर्देश दिया। निर्देश के अनुसार, स्टाफ ने खड़े होकर काम किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर हो रही है तारीफ: कर्मचारियों को लापरवाही के लिए दी गई सजा की हर तरफ तारीफ की जा रही है। लोग इस पर अलग-अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं। कई लोगों की कहना है कि इस तरह अफसर यदि कर्मचारियों को सजा दें तो कर्मचारी अपने काम के प्रति लापरवाह नहीं रहेंगे।

साथियों बात अगर हम बुजुर्गों के लिए एक एक्सट्रासिटी के समकक्ष कानून, सूचीगत जातियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 2019 के समकक्ष बुजुर्गों के सम्मान के लिए कानून बनाने की करें तो जिस तरह सामाजिक सौहार्दपूर्णता समाप्तता को कायम रखने के लिए एस्ट्रासिटी (अमेंडेड) कानून 2019 बनाया गया है जिसका डर हमेशा उपद्रवी लोगों में बना रहता है या फिर कभी नए फौजदारी अधिनियम 2023 में क्राइम को रोकने अनेक धाराओं का डर लोगों में बना हुआ है उसी तर्ज पर मेरा सुझाव है कि लोकसभा के शीतकालीन सत्र या फिर अगले महीने 2025 के बजट सत्र में बुजुर्गों के साथ होने वाली क्रूरता दुष्टपरिणाम दुर्व्यवहार अपमान व दुष्कार पर लगाम लगाने के लिए वरिष्ठ नागरिक (विधेयक 2024 बनाकर पेश किया जाए जिसे सभी पार्टियाँ एक मत होकर 544/0 मतदान से पारित करेंगे) ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। साथियों बात अगर हम 20 दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाले शीत सत्र या जनवरी 2025 के चौथे सप्ताह से शुरू होने वाले बजट सत्र में प्राथमिकता से इस विधेयक को अधिसूचित करने की करें तो, हम प्रस्तावित कानून में वरिष्ठ



बुजुर्ग को खड़ा रखा, बाबुओं को सजा, IAS का ये काम वायरल

नागरिक ( कार्यालयों में चकरे खिलाना अत्याचार अपमान दुर्व्यवहार निवारण) विधेयक 2024 की जरूरत है, हमारा देश महान सतानों की भूमि है, यहां शासकीय व निजी कार्यालयों में बुजुर्गों दिव्यांगों व सामान्य नागरिकों की उचित देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन पीड़ादायक है कि नैतिक मूल्यों में इस कदर गिरावट आ गई है कि अपना सुख-चैन व भ्रष्टाचार के बल पर, अपने परिवार को आरामदायक जिंदगी देने आम नागरिकों को अपने कार्यालय में टेबल के चक्कर काटने के लिए छोड़ देते हैं, जो न सिर्फ दुखद है, बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों में निरंतर आ रही गिरावट का प्रतीक भी है। हमारे सामाजिक

मूल्यों में तेजी से आ रहे बदलाव की वजह से आज बुजुर्गों को अपने छोटे-छोटे कामों के लिए शासकीय कार्यालय के चकरे काटने, करना काम नहीं होने पर अदालतों की शरण में आना पड़ रहा है, इस तरह की उर्दू शासकीय कर्मचारियों को सजा के रूप में आदेशी अदालत दे रही हैं, लेकिन यह सिलसिला बदस्तूर जारी है सामाजिक मूल्यों में आ रहे हास का ही नतीजा है कि दर बरदर की ठोकरें खाने के लिये छोड़ दिया जा रहा है या फिर सुरक्षित व जल्द काम करने के लिए हरे पीलों को अपेक्षा की जाती है, लेकिन पीड़ादायक है कि नैतिक मूल्यों में इस कदर गिरावट आ गई है कि अपना सुख-चैन के लिए आम जनता युवा, बुजुर्गों

और दिव्यांगों को भी चकरे खिलाने जाते हैं जो न सिर्फ दुखद है, बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों में निरंतर आ रही गिरावट का प्रतीक भी है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि शाबाश ऑफिसर! - ऑफिस में बुजुर्ग शख्स को इंतजार करवाया - बॉस ने स्टाफ को दी अनोखी सजा- मरते दम तक याद रखेंगे डिजिटल युग में हर सरकारी व निजी कार्यालयों के अधिकारियों को इस अधिकारी से सीख लेने की जरूरत सरकारी कार्यालय में छोटे-छोटे कामों के लिए कर्मचारियों द्वारा जनता को चकरे लगवाने के लिए सजा का अध्यादेश लाना जरूरी है।

- सौजन्य -

ईवी ड्राइव द फ्यूचर



## एमबीएम यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिक वाहनों पर करेगी शोध, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की होगी स्थापना

परिवहन विशेष न्यूज

एमबीएम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, जिसमें न केवल ईवी पर शोध होगा, बल्कि इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को पढ़ाई में भी यह विषय शामिल किया जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभागाध्यक्ष डॉ. एमके भास्कर ने बताया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ईवी वाहनों की डिजाइन, बैटरी की दक्षता बढ़ाने, चार्जिंग स्टेशन और ईवी के विभिन्न घटकों पर शोध किया जाएगा। इसके अलावा शोध का मुख्य फोकस राजस्थान जैसे गर्म प्रदेशों में बैटरी की दक्षता बढ़ाने पर रहेगा। इसके लिए अलग से भवन और ईवी प्रयोगशाला बनाई जाएगी और उपकरण लाए जाएंगे।

फिलहाल 50 किलोवाट की बैटरी से सर्दियों में 300 किलोमीटर चलने वाला ईवी वाहन जून तक 200 किलोमीटर का माइलेज देने लगता है। इसके चलते चार्जिंग पर अतिरिक्त खर्च आता है। विभागाध्यक्ष ने बताया कि इसके लिए बैटरी के कूलिंग सिस्टम का प्रोटोटाइप तैयार कर उसे अपग्रेड किया जाएगा, ताकि गर्मियों में यह ज्यादा कारगर हो सके। इस समय पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी की लागत कम करने पर फोकस किया जा रहा है। एमबीएम यूनिवर्सिटी के एक्सीलेंस सेंटर में बैटरी की लागत कम करने पर रिसर्च भी की जाएगी। फिलहाल सभी बैटरी लिथियम आयन पर फोकस हैं। इस पर भी रिसर्च की जाएगी। इसके अलावा दोपहिया और चार पहिया वाहनों की डिजाइन पर भी ध्यान दिया जाएगा।



## ईवीएक्सपो 2024 में पिछली बार से ज्यादा ब्रांड

EV EXPO 2024

2021 & 22 December

21st EVEXPO DELHI 2024

Go Powered By: OLIVE

In Association with: KHALSA

20 21 22 December 2024

Hall No- 1 & 2, Pragati Maidan, New Delhi-110001

Focus Industries:

- 2, 3, 4 wheeler and Bus (Electric vehicle manufacturers)
- Electric Vehicle parts and component manufacturers
- Commercial, Cargo, Passenger and Personal Electric Vehicles
- Battery Technology Companies
- Branding Solution Providers (Name plates, screen printers etc.)
- Insurance Companies
- Accessories Manufacturer
- Homologation/ Testing Agencies
- Charger Manufacturer
- Bank and Financial Institutions

21st EVEXPO DELHI 2024

JOIN THE INITIATIVE TOWARDS POLLUTION FREE NATION

Co Powered Partner: KHALSA, OLIVE

Our Partners:

Title Partner: KHALSA	Co Powered Partner: OLIVE	Associate Partner: EV	Activity Partner: 3511
Entry & Onsite Partner: KHALSA	Lanyard Partner: KHALSA	Two Wheeler Partner: EV	Lanyard Partner: KHALSA
Registration Partner: RAYS	Lanyard Partner: TNR	Lanyard Partner: MA X IM	Lighting Partner: SAFARI
Pioneer Partner: ACCESS TO POWER	Lanyard Partner: ACCESS TO POWER	Knowledge Partner: EASTMAN	Lead Mfg Connectivity Partner: AT

20 21 22 December 2024

Entry From Gate No-4, 6 & 10

Hall No- 1 & 2 Pragati Maidan, New Delhi-110001

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान, भारत मंडप में इस साल एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम दर्ज कराने जा रही है। भारत मंडप में 20 से 22 दिसंबर के बीच भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय ईवीएक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। यहां होने वाले ईवीएक्सपो में इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा, हाइब्रिड वाहन, ऑटोमोटिव कम्पोनेंट्स, ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर, वित्तीय कंपनियों, एसेसरीज, बैटरी मैनेजमेंट और स्टोरेज सिस्टम जैसे उत्पाद भी प्रदर्शित किए जाएंगे। इस ईवीएक्सपो का मकसद इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को व्यापार उद्योग और अंतिम उपभोक्ताओं से मिलने का मौका देना और नेटवर्किंग करना है।

ईवीएक्सपो के संयोजक राजीव अरोड़ा ने ईवी ड्राइव द फ्यूचर को बताया कि आज के बदलते तकनीक के दौर में आईसी इंजन वाले यानी पेट्रोल व डीजल

वाहनों के बजाए इलेक्ट्रिक एवं सौर ऊर्जा से चार्जिंग वाहनों के साथ हाइब्रिड, एथनॉल, मेथनॉल, बायो-फ्यूल और जैव-ईंधन जैसे वैकल्पिक ईंधन की डिमांड अधिक हो रही है, जो प्रदूषण मुक्त भारत के लिए लोग ई-व्हीकल को अपना रहे हैं। इस आयोजन में ईवी उद्योग के पेशेवरों, उस्ताहा लोगों और प्रमुख हितधारकों सहित 50,000+ से अधिक आगंतुकों के आने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि ईवीएक्सपो में करीब 200 से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटोमोटिव से जुड़ी भारतीय और विदेशी कंपनियों के साथ-साथ ईवी वगैरह के स्टार्टअप भी हिस्सा ले रहे हैं। ईवीएक्सपो 10:00 बजे से 18:00 बजे तक चलेगा। इसमें बी2बी के साथ-साथ तीनों दिन आम जनता के लिए फ्री एंट्री भी रहेगी। इस ईवीएक्सपो में चीन और जापान की नामी कंपनियों भी अपनी नई ईवी से जुड़ी टेक्नॉलॉजी को प्रदर्शित करेंगी।

ईवीएक्सपो इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ा राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय शो का एक भव्य मंच है जो वर्ष 2015 से लगातार इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को अपने उत्पादों और तकनीक को दिखाने का मौका देने के उद्देश्य से आयोजित करते आ रहा है।

ऑल्टियस ऑटो सोल्युशंस द्वारा आयोजित ईवीएक्सपो के 21वें संस्करण को प्रमुख उद्योग निकायों द्वारा समर्थित किया गया है, जिसमें आईकेए (ICAT), इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन (EVF), इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन (IFEVA) और इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी (IFGE) हैं।

ईवीएक्सपो शो में टाइटल पार्टनर खालसा ईवी, को-पावर्ड सुपीरियर इंक ऑलिव, एसोसिएट पार्टनर सीबीआई गोल्ड इंटरनेशनल, एक्टिविटी पार्टनर उडान, बैटरी एण्ड ड्राइवटैक पार्टनर लिवागार्ड एनर्जी टेक्नॉलॉजी, लैनयार्ड

पार्टनर टीएनआर, टू-व्हीलर पार्टनर मैक्सिम ई-व्हीकल्स, लैनयार्ड पार्टनर सफारी ई-रिक्शा, रजिस्ट्रेशन पार्टनर रेंज ग्लोबल एनर्जी, लैनयार्ड पार्टनर एक्ससेस टू पावर एक्सपीरिमेंटल पावर, लैनयार्ड पार्टनर इस्टेमन ऑटो एण्ड पावर, लाइटिंग पार्टनर केके लाइटिंग, पार्यनियर पार्टनर स्पीगो-मोरनी, अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय निर्यात होमलोगेशन पार्टनर एटीएसआईपीएल, नॉलेज पार्टनर राजुलेक्स, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पार्टनर सिटीलाइफ के अतिरिक्त डुकुराल इलेक्ट्रिक वाइक्स, लोहिया, टेरा मोटर्स, डायमंड, प्लॉडिट, कैपटेक, वंदे भारत, पायलट, आरजू, बुलॉक ई-रिक्शा, ट्रम्प ईवी टू-व्हीलर पार्ट्स, मर्करी ईवी टेक, काइनेटिक कम्प्युनिकेशन्स, बाहुबली, सहित 200 कंपनियों के अलावा बैटरी मैनेजमेंट, स्टोरेज सिस्टम, चार्जिंग उपकरणों, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिवाइस, सॉफ्टवेयर जैसी नामी कंपनी शामिल हो रही हैं।

## ईवी सहित सभी पुराने वाहन होंगे महंगे



परिवहन विशेष न्यूज

भारत में पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों का बाजार पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। पुराने वाहनों की खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए यह एक सस्ता विकल्प होता है, जिससे वे कम कीमत पर अच्छा वाहन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि अब यह सेक्टर महंगा हो सकता है।

जोएसटी कार्सिल अगले कुछ दिनों में पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों पर जोएसटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% करने पर विचार कर सकती है। जोएसटी कार्सिल की फिटमेंट कमेटी ने पुराने वाहनों पर जोएसटी दर बढ़ाने की सिफारिश की है, जिसे 12% से बढ़ाकर 18% किया जा सकता है। यह परिवर्तन पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों के लिए लागू हो सकता है और इसका असर इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी पड़ सकता है।

वर्तमान में इन वाहनों पर जोएसटी की दर सप्ताह के मार्जिन के आधार पर तय होती है, जिससे टेक्स का बोझ अपेक्षाकृत कम होता है। लेकिन अब इस दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, जिससे पुराने वाहनों की कीमतों में

वृद्धि हो सकती है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी बदलाव हो सकता है। वर्तमान में नए इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% जोएसटी लागता है ताकि इस क्षेत्र में ग्राहकों को बढ़ावा दिया जा सके, लेकिन सेकेंड-हैंड ईवी पर अगर 18% जोएसटी लागू किया जाता है, तो यह इन वाहनों को और भी महंगा बना सकता है।

खासकर उन ग्राहकों के लिए यह एक बड़ा झटका हो सकता है, जो सस्ते से सेकेंड-हैंड ईवी खरीदने का विचार कर रहे हैं। इस बदलाव से सेकेंड-हैंड ईवी वाहनों की बिक्री कम हो सकती है, और यह मार्केट के आकर्षण को भी प्रभावित कर सकता है। पुरानी गाड़ियों की मरम्मत इससे पहले से ही, रबरखवाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इनपुट पावर्स और सर्विसेज पर 18% जोएसटी लागू होता है। इसका मतलब यह है कि पहले से ही इन वाहनों की रखरखाव लागत में बढ़ोतरी हो चुकी है। यदि जोएसटी दर बढ़ाई जाती है, तो यह और भी अधिक महंगा हो सकता है, जिससे इन वाहनों की कुल कीमत में और इजाफा होगा।

इस बदलाव से सेकेंड-हैंड वाहनों के खरीदारों की संख्या में गिरावट आ सकती है और वाहन की बिक्री पर इसका नकारात्मक असर हो सकता है। अभी जो जोएसटी दरें लागू हैं, उनमें 1200 cc या उससे अधिक की इंजन क्षमता वाले पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी से चलने वाले वाहनों पर 18% जोएसटी लागता है। इसी तरह 1500 सीसी या उससे अधिक इंजन क्षमता वाले डीजल वाहनों पर भी 18% जोएसटी है। इसके अलावा 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स पर भी 18% जोएसटी लागू है। ऐसे में अगर सेकेंड-हैंड वाहनों पर जोएसटी दर बढ़ाई जाती है, तो यह इन वाहनों के लिए मौजूदा टैक्स ढांचे के अनुरूप हो सकता है।

यह बदलाव सेकेंड-हैंड इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि इससे उनका आकर्षण कम हो सकता है। जोएसटी कार्सिल की 55वीं बैठक 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य वित्त मंत्रियों के साथ अन्य

अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा सकता है, जैसे कि टर्म लाइफ इश्योरेंस पॉलिसी पर जोएसटी में बदलाव, हेल्थ इश्योरेंस प्रीमियम पर छूट, जोएसटी स्लैब की समीक्षा, और पुराने वाहनों पर जोएसटी दर में वृद्धि पर चर्चा की जा सकती है।

इस बैठक के दौरान पुरानी और इस्तेमाल किए गए वाहनों के बाजार पर असर डालने वाले कई बड़े फैसले किए जा सकते हैं। अगर पुराने वाहनों पर जोएसटी दर बढ़ाई जाती है, तो इसका असर भारतीय वाहन बाजार पर व्यापक रूप से पड़ सकता है। पहले से ही जोएसटी की दर 18% लग रही है, लेकिन अगर इसे बढ़ाकर 18% किया जाता है, तो यह ग्राहकों को पुराने वाहनों की खरीदारी में झटका दे सकता है। खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी पुरानी कार या बाइक को बेचने के बाद दूसरी सेकेंड-हैंड वाहन खरीदने की योजना बना रहे थे। इसके अलावा, यह इलेक्ट्रिक वाहनों के सेकेंड-हैंड बाजार के लिए भी एक चुनौती हो सकता है, क्योंकि इससे उनके लिए आकर्षण कम हो सकता है।

## स्कोडा एनाक फेसलिफ्ट की आई पहली झलक, नए डिजाइन समेत दिखे कई फीचर्स

परिवहन विशेष न्यूज

स्कोडा ने Enyaq और Enyaq Coupe EV के फेसलिफ्ट वर्जन के पहले एक्सटीरियर स्केच को जारी किया है। इन स्केच में गाड़ी का नया डिजाइन देखने के लिए मिला है। इसमें बड़े बड़े अलॉय व्हील और डोर हैंडल देखने के लिए मिले हैं। साथ ही स्केच में डार्क क्रोम एक्सटेंड शार्प टियर-ऑफ एज और सिग्नेचर C-शेड टेल लाइट्स भी देखने के लिए मिला है।

स्कोडा ने अपने फेसलिफ्टेड Enyaq और Enyaq Coupe EV के पहले एक्सटीरियर स्केच जारी किए हैं। यह स्केच नई मॉडल के सॉलिड डिजाइन लैंग्वेज का दावा करते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रिक कार को भारतीय बाजार के लिए सीबीयू के रूप में लाएंगी। यह 2024 में यूरोप की सबसे ज्यादा बिकने वाली बीईवी में से एक है। आइए जानते हैं कि Skoda Enyaq फेसलिफ्ट के स्केच में क्या कुछ नया देखने के लिए मिला है।

**Skoda Enyaq facelift: कैसा है डिजाइन**  
स्कोडा एनाक में कंपनी का नया लेटरमार्क लोगो देखने के लिए मिला है, साथ ही चेक ब्रांड जिसे टेक-डेक फेस भी दिया गया है। इसमें आइटोइंग मॉडल की तुलना में बहुत पतली ग्रिल दी गई



है, जो DRLs के साथ मिलती है। इसके हेडलाइट यूनिट सीधे DRLs के नीचे दी गई है और इसके बंपर में एयर इन्टेक के जरिए फ्रंट किया गया है। साइड स्कर्ट और रियर बंपर के साथ सिल्वर पैनल में इसका स्केच जारी किया गया है।

इसमें मौजूदा Enyaq की तरह ही कूप फॉर्म में लाया जाएगा। इसके टीजर इमेज में बाँड़ी पर शार्प लाइन्स के साथ एक सिल्यूट देखने के लिए मिला है। इसमें एक ब्लैक रूफ भी देखने के लिए मिला है। इसके स्केच में बड़े अलॉय व्हील और डोर हैंडल भी देखने के लिए मिले हैं। इसके अलावा, स्केच में डार्क क्रोम एक्सटेंड, शार्प टियर-ऑफ एज और सिग्नेचर C-शेड टेल लाइट्स भी देखने के लिए मिला है।

**Skoda Enyaq का इंडिया लॉन्च प्लान**  
स्कोडा की तरफ से पुष्टि की

गई है कि Enyaq फेसलिफ्ट और इसके कूप-समकक्ष को साल 2025 के आखिरी में पेश किया जाएगा। स्कोडा ने पिछले Enyaq iV को 2024 भारत में पेश किया था। जिसे देखते हुए उम्मीद है कि अगले साल जनवरी में होने वाले ऑटोएक्सपो में उसी मॉडल को कंपनी दोबारा दिखा सकती है।

**टेस्टिंग के दौरान हो चुकी है स्पाट**  
स्कोडा Enyaq को अभी तक कई बार टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया जा चुका है। टेस्ट मूल्य में 513 फीसदी तक की WLTP रेंज वाली 77 kWh बैटरी, 125 kW तक DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जैसे फीचर्स का पता चला था। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि इसमें लगा हुआ मोटर 265 hp की पावर जनरेट करेगा। वहीं, यह महज 6.9 सेकेंड में 0 से 100 kph तक की रफ्तार पकड़ सकती है।

## मल्टीबैगर ईवी स्टॉक में FII की तूफानी खरीदारी, 90 रुपये से कम कीमत पर कारोबार बढ़ रही कंपनी

परिवहन विशेष न्यूज

पिछले तीन दिनों से शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट के दौरान निफ्टी ने 24200 का स्तर देखा। पिछले कुछ सत्रों में बाजार में धैर्य सेलिंग देखने को मिल रही है, जिसका असर कई लाज-कैप स्टॉक में लगातार बिकवाली के रूप में देखने को मिल रहा है।

इन दौरान बाजार में कुछ ऐसे शेयर भी हैं, जिसमें विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। FII अक्सर बिकवाली के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन हाल ही में FII ने ईवी स्टॉक मर्करी ईवी-टेक लिमिटेड में मल्टीबैगर की और कंपनी के 30 लाख शेयर खरीदे।

मर्करी ईवी-टेक लिमिटेड के शेयर बुधवार, 18 अक्टूबर को 86.30 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे थे। कंपनी का मार्केट कैप 1.64 हजार

करोड़ रुपये है।

मर्करी ईवी-टेक अपने व्यवसाय विस्तार के लिए एक नई सहायक कंपनी बना रही है। मर्करी ईवी-टेक लिमिटेड ने 17 दिसंबर, 2024 को आयोजित अपनी बोर्ड मीटिंग में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एक नई सहायक कंपनी, रंग्लोबल मर्करी कंटेनर प्राइवेट लिमिटेड को शामिल करने का संकल्प लिया। कंपनी की अधिकृत पूंजी 10,00,000 रुपये और चुकता पूंजी 10,00,000 रुपये होगी।

मर्करी ईवी-टेक लिमिटेड 60,000 इक्विटी शेयरों की सदस्यता लेकर नई सहायक कंपनी में निवेश करेगी, जो चुकता पूंजी का 60 प्रतिशत है, जिसका अंकित मूल्य 10 रुपये है, कुल निवेश 6,00,000 रुपये है।

ग्लोबल मर्करी कंटेनर प्राइवेट लिमिटेड का प्राथमिक व्यावसायिक उद्देश्य आईएसओ शिपिंग कंटेनर, कंटेनरों के लिए शीपिंग कवर तंत्र, कंकाल

कंटेनर और विशेष प्रयोजन कंटेनर सहित कंटेनरों का निर्माण और सौदा करना होगा।

यह मर्करी ईवी-टेक लिमिटेड के व्यवसाय की लाइन के अनुरूप है। अधिग्रहण में कोई संबंधित पक्ष लेनदेन शामिल नहीं है और इसके लिए किसी सरकारी या नियामक अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। कंपनी को उम्मीद है कि वह लागू कानूनों द्वारा अनुमत समय सीमा के भीतर सहायक कंपनी का निगमन पूरा कर लेगी।

मर्करी ईवी-टेक लिमिटेड को पहले मर्करी मेटल्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। यह भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक विंटेज कार, इलेक्ट्रिक गोल्फ कार और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में शामिल है। कंपनी ने तिमाही नतीजों (Q2FY25) और अर्ध-वार्षिक नतीजों (H1FY25) में सकारात्मक आंकड़े दर्ज किए हैं।



## पुरुष प्रताड़ना का औचित्य



डा. वरिंद्र भाटिया

पुरुष आयोग की मांग कर रही एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि हमारे समाज में जब पुरुष के ऊपर अत्याचार होता है तो उनकी सुनने वाला भी कोई नहीं होता है। वह कहती है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं, जिनमें पुरुष अपनी ही पत्नियों से प्रताड़ित रहते हैं। पत्नी के द्वारा गलत आरोप लगाकर पारिवारिक न्यायालय में केस दर्ज कराया जाता है। इस तरह के केसों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। इसके पीछे कई कारण हैं। उन्होंने कहा कि हर महिला या हर पुरुष एक समान नहीं होता है। कुछ महिलाएं सीमाओं का उल्लंघन करती हैं।

पुरुष प्रताड़ना से जुड़ा ताजा मुद्दा पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष (34) ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि वह अपनी पत्नी की ओर से लगाए गए आरोपों से परेशान हो चुका था। उसका आरोप था कि एक के बाद एक धाराएं उस पर और उसके परिवार वालों पर लगाई गईं। हमारे समाज में सिर्फ अतुल का ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जिनमें पुरुषों ने महिलाओं के आरोपों से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली। आज पुरुष उत्पीड़न का मुद्दा गंभीर बना हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक, पुरुष उत्पीड़न के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पुरुष अक्सर अपने उत्पीड़न की बात खुलकर कहने में हिचकते हैं। समाज में बनी इस धारणा के कारण कि महिलाएं ही पीड़ित होती हैं, पुरुषों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। मनोविज्ञानी कहते हैं कि महिलाओं की प्रमुख शिकायतें अक्सर पुरुषों के नशे में हिंसक होने, विवाहेतर संबंध रखने या परिवार की उपेक्षा करने से जुड़ी होती हैं। इन पर कार्रवाई होती है, लेकिन पुरुषों की ऐसी शिकायतों को क्यों उतनी तवज्जो नहीं मिलती। गौरतलब है कि समाज में महिलाओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए कई सरकारी कानून बनाए गए हैं। इनसे महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर लगाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पुरुषों के उत्पीड़न का मुद्दा अब भी गंभीर अन्देखी का शिकार है। पुरुष उत्पीड़न का सीधा असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। कई बार यह हताशा उन्हें आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर कर देती है।

बेंगलुरु के अतुल सुभाष का मामला इसका ताजा उदाहरण है। भारत में अभी तक ऐसा कोई सरकारी अध्ययन या सर्वेक्षण नहीं हुआ है जिससे इस बात का पता लग सके कि घरेलू हिंसा में शिकार पुरुषों की तादाद कितनी है। लेकिन कुछ गैर सरकारी संस्थान इस दिशा में जरूर काम कर रहे हैं। 'सेव इंडियन फेमिली फाउंडेशन' और 'माई नेशन' नाम की गैर सरकारी संस्थाओं के एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि भारत में नब्बे फीसदी से ज्यादा पति तीन साल की रिलेशनशिप में कम से कम एक बार घरेलू हिंसा का सामना कर चुके होते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पुरुषों ने जब इस तरह की शिकायतें पुलिस में या फिर किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर करनी चाही तो लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया और शिकायत करने वाले पुरुषों को हंसी का पात्र बना दिया गया। कुछेक महिलाओं द्वारा पुरुषों को प्रताड़ित करने से, पुरुषों द्वारा आत्महत्या के



मामलों में वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश में पुरुषों की आत्महत्या की दर महिलाओं की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है। इसके पीछे तमाम कारणों में पुरुषों का घरेलू हिंसा का शिकार होना भी बताया जाता है जिसकी शिकायत पुरुष किसी फोरम पर कर भी नहीं पाते हैं। उनमें सबसे बड़ा तर्क यह है कि महिलाओं को सुरक्षा देने के जो कानून बने हैं, उनके दुरुपयोग से पुरुषों को प्रताड़ित किया जाता रहा है। मौजूदा कानून धारा 498-ए, अमरीका के जिस कानून से प्रेरित होकर यह कानून बनाया गया था, वह अमरीकी कानून जेंडर निरपेक्ष है और उसमें पुरुषों की प्रताड़ना के मामले भी देखे जाते हैं। पिछले 20 वर्षों से पुरुष प्रताड़ना के केस तेजी से बढ़े हैं। आज इंजीनियर अतुल सुभाष के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और के साथ ऐसा होगा। ऐसे में सरकार को पुरुषों के हित में कोई न कोई कानून जरूर बनाना चाहिए। अतुल पढ़े लिखे शख्स थे। उन्होंने अपनी आपबीती पूरी दुनिया को सुनाई, फिर उसके बाद उन्होंने आत्महत्या का कदम उठाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जिनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। वे अंदर ही अंदर परेशानियों से लड़ते, झगड़ते व जुझते हैं। केस के चक्कर में घर, जमीन, जायदाद सब बिक जाता है।

लेकिन, किसी को कानोंकान खबर तक नहीं होती है। हमें उन बेकसूरों को भी इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठानी है, ताकि भविष्य

में कभी किसी दूसरे अतुल के साथ इस तरह की घटना न हो। इस समय ऐसे मामलों में काफी वृद्धि हो रही है, लेकिन क्या इन घटनाओं के कारण झूठे हैं या नहीं, इसका जवाब तो आत्मदर्शन से भी आसानी से मिल सकता है। महिलाओं द्वारा पुरुषों पर हिंसा आज एक आम समस्या बन गई है। इसमें आर्थिक, शारीरिक, यौन और भावनात्मक शोषण के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार भी शामिल है, जो किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। पुरुष और महिलाएं भी लिंग आधारित हिंसा का शिकार हैं। भारत जैसे देश में, जो सदियों से पुरुष प्रधान रहा है, लोगों के लिए यह विश्वास करना कठिन है कि पुरुष भी महिलाओं की तरह घरेलू हिंसा के शिकार हो सकते हैं। इसका एक कारण यह हो सकता है कि भारत में किसी भी कानून में पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा को मान्यता नहीं दी गई है। हालांकि, आम धारणा के विपरीत, महिलाओं द्वारा मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होने वाले पुरुषों की संख्या बढ़ रही है। देश में मौजूदा कानूनों को देखते हुए, ऐसा कोई खास कानून नहीं है जो पुरुषों को अंतरंग साथी की हिंसा से बचाता है। भारतीय संविधान कहता है कि सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर पुरुष इसका अपवाद कैसे हो सकते हैं? इस क्षेत्र में घरेलू हिंसा को रोकने और कम करने के लिए, लिंग तटस्थ कानून लागू किए जाने चाहिए और लिंगवादी कानून नहीं बनाए जाने चाहिए। पुरुषों

के खिलाफ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना तो अब संवेदनहीन मुद्दा है, न ही इस पर बात करना महिला अधिकारों का किसी प्रकार का अतिक्रमण है। जहां तक पुरुषों के उत्पीड़न का प्रश्न है, इस पर बात करना मानव अधिकारों का, समाज में संतुलन बनाए रखना है।

एक देशी डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'मार्टर्स ऑफ मैरिज' में ऐसे पुरुषों की कहानी बर्बाद की गई है जिन्होंने झूठे केस में फंसाए जाने के बाद आत्महत्या कर ली। अतुल सुभाष का मामला इससे मिलता जुलता है। पुरुष आयोग की मांग कर रही एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि हमारे समाज में जब पुरुष के ऊपर अत्याचार होता है तो उनकी सुनने वाला भी कोई नहीं होता है। वह कहती है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं, जिनमें पुरुष अपनी ही पत्नियों से प्रताड़ित रहते हैं। पत्नी के द्वारा गलत आरोप लगाकर पारिवारिक न्यायालय में केस दर्ज कराया जाता है। इस तरह के केसों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। इसके पीछे कई कारण हैं। उन्होंने कहा कि हर महिला या हर पुरुष एक समान नहीं होता है। कुछ महिलाएं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती हैं, उनके मन मुताबिक जब चीज नहीं होती है तो उस पर वह तलाक के लिए पारिवारिक न्यायालय जाती हैं। केस दर्ज करते समय तमाम धाराओं के साथ पति पर केस दर्ज करा देती हैं। क्या ऐसे मामले झूठ होते हैं या सच, इसका हम सबको आत्मज्ञान होना चाहिए। अतुल को न्याय अवश्य ही मिलना चाहिए।

## तबले ने खोया उस्ताद

तबले ने अपना उस्ताद खो दिया। तबले की एक खास ध्वनि, थाप, ताल खामोश हो गई। एक बिछौना सूना हो गया और एक आत्मा बिछुड़ कर, सुदूर, किसी शून्य में विलीन हो गई। तबले का जीवंत रिश्ता आज मुरझा गया। बहुत कुछ बिखर कर रह गया। चार ग्रैमी अवार्ड, तीन पद्म सम्मान, अमरीकी राष्ट्रपति के 'व्हाइट हाउस' में थाप, ताल और थिरकन का प्रदर्शन, चार पीढ़ियों के शास्त्रीय संगीत को लयात्मक संगत देने की असंख्य यादें अनाथ, अकेली हो गईं। तबले को नई-नई भाषाएं देने वाला और किसी भी ताल, थाप में अचानक 'तिहाई' मारने वाला उस्ताद आज थम गया, खामोश हो गया, मानो एक दुनिया 'शांत' हो गई हो! तबला-वादन के उस्ताद जाकिर हुसैन ने अपने वाद्य को उसी तरह जिया, जिस तरह पंडित रविशंकर ने सितार को, पंडित जसराज ने शास्त्रीय गायन को, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने बांसुरी को, पंडित शिवकुमार शर्मा ने संतूर को, उस्ताद अमजद अली ने सरोद और उसके संगीत को जिया। जाकिर अकेले, अलबेले, अद्भुत तबला-उस्ताद थे, जिन्होंने इन उस्तादों के संगीत को लयात्मक पूरकता दी। जाकिर एक वाद्य-यंत्र के उस्ताद ही नहीं, कोई अवतार लगते थे, लिहाजा मात्र तीन साल की उम्र में ही तबले पर थाप लगाने और उंगलियों की थिरकन की जादुई शुरुआत की। इस उम्र में तो बच्चे नाक साफ करना भी नहीं सीख पाते। उस्ताद के पिता अल्ला रक्खा खां खुद 'उस्ताद तबला वादक' थे और जाकिर ने उनके साथ कई जुगलबंदियां पेश की थीं, लेकिन 'नन्हा उस्ताद' अपनी समकालीन, पुरानी पीढ़ियों और उनके समय के बहुत पार चला गया। जाकिर ने संगीत के सहायक वाद्य को मुख्य वाद्य बना दिया, नतीजतन आज दुनिया भर में तबले की 'खास पहचान और प्रतिष्ठा' है।

जाकिर तबले के पर्याय बन चुके हैं, लेकिन भीतर से एक दुखद, पीड़ित 'आह' निकलती है-उस्ताद जाकिर हुसैन! बेशक उस्ताद 73 साल की उम्र में ही हमें छोड़ कर चले गए, उनका पार्थिव शरीर 'मिट्टी' हो गया, वह 'सुपुर्द-ए-खाक' हो गए, लेकिन तबला-वादन की जो लंबी विरासत, संगीत की खूबसूरती, तबले की कला की एक सुदूर परंपरा और यादों की लंबी कडियां छोड़ गए हैं, उन्हें 'मृत' कैसे माना जा सकता है? संगीत के पंडित, महाराज और उस्ताद, अपने-अपने कालखंडों में, उतने लोकप्रिय नहीं हो पाए, जितनी जन-स्वीकृति और मान्यता उस्ताद जाकिर हुसैन ने हासिल की। उन्होंने तबले को भी जन-जन का वाद्य यंत्र बना दिया। घर-घर और दफ्तरों में आम आदमी जब किसी सतह पर थाप देने लगता है, तो उसे तुरंत जाकिर हुसैन से जोड़ दिया जाता है। हालांकि वह गंधर्व की भाषा होती है, लेकिन तबला जाकिर हुसैन से ही की जाती है। बेशक एक लंबे अंतराल से उस्ताद अमरीका में ही बसे रहे, लेकिन वह आखिरी सांस तक हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी संगीत को ही जीते रहे। आज दुनिया भर के कलाकार, उनके समकालीन गायक और वाद्य बजाने वाले भी उन्हें याद कर रहे हैं। असंख्य संस्मरण उनके साथ जुड़े हैं। बहरहाल आज वह हमारे बीच जीवंत नहीं हैं, लेकिन जिन गायनों के साथ उन्होंने तबले की थाप, ताल पर संगत दी थी, वे हमें हमेशा याद दिलाते रहेंगे। उस्ताद जीवंत रूप में हमारे बीच होंगे, लिहाजा कलाकार कभी मरा नहीं करते।

## शीत ऋतु की टिडुरन का एहसास करें

गलगल को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़े कर लेते हैं और हरा धनिया, लहसुन या लहसुन की हरी पत्तियां, अदरक, गरम मसाला, हरी मिर्च, लाल मिर्च, पुदीने की खूब सारी चटनी बनाते हैं और गुड़ या चीनी भी डालकर कटे हुए गलगल में अच्छे से मिला लेते हैं

ऋतु परिवर्तनशील है। भारत में छह ऋतु पाई जाती हैं- बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शीत, हेमंत और शिशिर ऋतु। भारत ही एक ऐसा देश है जहां छह ऋतुओं को अनुभव करने का आनंद प्राप्त होता है और यह आनंद केवल उत्तरी भारत में ही प्राप्त हो सकता है। अन्य अधिकतर देशों में केवल चार ऋतुएं ही पाई जाती हैं। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु। यहां हम केवल शरद ऋतु का ही वर्णन करेंगे। भारतीय वैदिक कैलेंडर के अनुसार भारत का नव वर्ष चैत्र मास से मनाया जाता है। ब्रह्मा जी ने इसी समय सृष्टि की रचना की थी। चैत्र मास में बसंत ऋतु आती है और वाक्येवी माता सरस्वती जी ने भी बसंत पंचमी के दिन अपनी वीणा की झंकार से सृष्टि को वाक शक्ति दी थी जिससे प्रत्येक वस्तु को शब्द ध्वनि प्राप्त हुई थी। चैत्र मास के बाद ही अन्य ग्यारह महीने अलग-अलग ऋतुओं के संग अठारहव्यां करके बीतते हैं। इन्हीं

महीनों के अनुसार कौनसी ऋतु किस-किस महीने आती है- 1. बसंत ऋतु- चैत्र से वैशाख महीना। फरवरी से मार्च। 2. ग्रीष्म ऋतु- ज्येष्ठ से आषाढ़। मार्च से जून। 3. वर्षा ऋतु- सावन से भाद्रपद। जुलाई से सितंबर। 4. शरद ऋतु- आश्विन से कार्तिक। अक्टूबर से नवंबर। 5. हेमंत ऋतु- मार्गशीर्ष से पौष।

दिसंबर से जनवरी। 6. शिशिर ऋतु- माघ से फाल्गुन। जनवरी से फरवरी। भारत के उत्तरी भाग में अक्टूबर से शरद ऋतु अपना खूब असर दिखाने लगती है। लोग गर्म कपड़े पहनना आरंभ कर देते हैं। परंतु समतल इलाकों जैसे पंजाब-हरियाणा में इन्हीं दिनों कम सर्दी होती है और अक्टूबर के अंत में धीरे-धीरे बढ़ती है। इसके विपरीत पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड अधिक रहती है और पर्वत की चोटियों में बर्फ गिरने के कारण चलने वाली शीत लहरें समतल क्षेत्र में अपने गुणों का अधिक प्रभाव दिखाती हैं। इसके कारण बहुत से जीव-जंतु सर्दी से बचने के लिए शीत निद्रा में चले जाते हैं, जैसे- सांप, मेंढक, चींटियां, छिपकलियां, गिलहरियां, खराशा, जंगली चूहे, गोंह, किरले, भालू, और भी ठंडे इलाकों में रहने वाले जीव-जंतु। हेमंत ऋतु- यह दिसंबर से जनवरी तक रहती है। इस समय सर्दी अपनी चरम सीमा पर होती

है। सर्दी से बचने के लिए लोग अनेक उपाय करते हैं। शरीर गर्म कपड़ों से अधिक भरा रहता है। सिर से पांव तक गर्म कपड़ों से लदे रहते हैं। सड़कों पर जगह-जगह पर लोग आग जलाकर ताप रहे होते हैं। घरों में भी लोग हीटर, ब्लोअर तथा गर्म पानी की बोतलों का प्रयोग करते हैं। बर्फीले इलाकों में जहां लंबे समय तक बर्फ रहती है, वहां के लोग सर्दी आने से पहले ही लकड़ी व अनाज का भंडारण कर लेते हैं तथा बकरे के मीठ को बड़ी मात्रा में सुखा कर रख लेते हैं।

वे एक बड़े कमरे में तंदूर जलाकर तापमान को बढ़ा लेते हैं और तंदूर पर खाना भी बना लेते हैं। यहां के मकान ईट-सीमेंट के नहीं होते हैं क्योंकि ऐसे मकान अधिक ठंड होने के साथ-साथ बर्फ में खराब भी हो जाते हैं। यहां के मकान केवल लकड़ी के बनाए जाते हैं जो बर्फीले मौसम में भी गर्म रहते हैं। यहां के लोग बड़ी मात्रा में भेड़-बकरियां पातले हैं जिससे सर्दी के मौसम में ऊन व मांस प्राप्त किया जा सके। ठंडे इलाकों में खानपान की विशेष ध्यान रखा जाता है। इस मौसम में गर्म तासीर का ही खाना खाया जाता है। तिल, अखरोट और बादाम से तैयार सिद्धू, मांस, मांस से तैयार मो-मो,



थुक्का, जुम्मा। दालों में कुलथ, मोठ तथा अन्य दालें व साग-सब्जियां, सूखे भेजे, मूंगफली। पेय पदार्थ में नमकीन चाय जिसकी चाय पत्ती एक विशेष प्रकार की होती है। देसी शराब, लुगड़ी इत्यादि। समतल इलाकों में भी साग-सब्जियां, चिचुरा, मोठ, अन्य दालें, कुचालू, घंड्याली, मीठ, मछली, चावल, मक्की, गेहूं की रोटी, चाय, कॉफी, शराब, सूखे भेजे, मूंगफली, पंजीरी, जिसे कहीं-कहीं सुड भी कहते हैं, ये सब खाद्य पदार्थ शरीर को गर्म रखने के लिए खाए जाते हैं। शिशिर ऋतु- यह ऋतु जनवरी से फरवरी

महीने में आती है। इसमें भी सर्दी चरम सीमा पर होती है, परंतु समतल इलाकों में 14 जनवरी यानी मकर संक्राति से सूर्य के उत्तरायण हो जाने के कारण मौसम में धीरे-धीरे बदलाव आना आरंभ हो जाता है, जिसमें धीरे-धीरे दिन भी बढ़ने लगते हैं और धीरे-धीरे टिडुरती सर्दी से गुलाबी सर्दी आने लगती है, परंतु पर्वतीय इलाकों में अभी भी सर्दी चरम सीमा पर होती है। पूरी सर्दियों में धुंध और कोहरे की घनी चادر से सूर्य की किरणें धरती पर 12.00 से 1.00 बजे तक नहीं पहुंच पाती हैं और दिन छोटे होने के कारण सूर्य जल्दी ही

अस्त भी हो जाता है, जिसके कारण धरती का तापमान न्यूनतम चला जाता है। मकर संक्राति से सूर्य के उत्तरायण होने से मौसम में बदलाव आने से धुंध और कोहरे का हटना आरंभ हो जाता है और सूर्य की चटकते लगा-लगा कर खाते हैं। इसमें एक तो विदामिन-सी प्रचुर मात्रा में होती है और यह तासीर में भी गर्म होता है। साथ ही इसके तीखे स्वाद से आंख-नाक बहने लगते हैं जिससे जुकाम में तुरंत फायदा मिलता है। बहरहाल ऋतु अनुसार ही साग-सब्जी को खाना चाहिए। विपरीत भोजन हानिकारक होते हैं।

## मानकों का झोल तो जिंदगी गोल

विजय गर्ग

सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक करते फेफड़ों का मन खरने के लिए अपने फेफड़ों में जरा कम घटिया हवा भरने निकला था कि सामने अपने नाक पर रुमाल रख अपना बिस्तर बांधे खड़े पता नहीं कहां जाने को आतुर बंधु दिखे तो विस्मय हुआ। उनको मुस्कुराते हुए भावभीनी विदाई देने से पहले उनके पास राम सलाम करने गया तो उनसे यों ही पूछ लिया, 'बंधु! सुबह सुबह कहाँ?' 'यार! लगता है अब ये शहर जीने लायक नहीं रहा। यहां की हवा मानकों से बहुत नीचे बह रही है।' 'मानकों के नीचे तो यहां बहुत कुछ है। तुम भी। मैं भी। तो क्या हम अपने को भी छोड़ दें? शहर में क्या सुविधा नहीं? पानी समय पर आता है। पेपर समय पर आता है। ताजी ताजी सब्जियां ऐसी मिलती हैं कि ऋण कूड़े के डेर पर सोई होने के बाद भी दुध की पतियां मोहल्ले मोहल्ले बह रही हैं। ढाबे ढाबे बटर के अक्षय भंडार भरें हैं। रोटी न बने तो जमेदो हाजिर है। ऐसे में मुझे तो ये शहर एक सौ दस प्रतिशत जीने के लायक लगता है। इतनी चकाचौध जो मेरे शहर में है, इतनी तो इंद्रपुरी में भी क्या ही

होगी? और एक तुम हो कि ऐसे शहर को न जीने लायक घोषित कर खिसके जा रहे हो?' 'बंधु! यहां रहने वालों की क्वालिटी तो गिरी ही हुई थी, पर अब यहां हवा की क्वालिटी भी गिर गई है। और तुम्हें तो पता है कि मैं हर चीज से समझौता करने का आदी हूँ, पर क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करता।' 'तो?' 'मैं वक्त से पहले मरना नहीं चाहता बंधु! इसलिए किसी ऐसे हिल स्टेशन पर जा रहा हूँ जहां कम से कम हवा तो क्वालिटी की मिले', कह उन्होंने अपनी जेब से एक रुमाल निकाल मुझे भी अपनी नाक पर रखने को दिया, पर मैं वह रुमाल अपनी नाक पर रखने के बदले ज्यों ही अपनी जेब में डालने को हुआ तो वे मुझ पर गुस्साते बोले, 'हद है यार!

वक्त से पहले मरने का शौक है क्या? मैंने तुम्हें रुमाल जेब में रखने के लिए नहीं, नाक पर रखने के लिए दिया है।' 'मिर! नाक पर रुमाल रखें वे जिनकी नाक कटी हो। नाक बंदतमीज से बंदतमीज की शान होती है। इसलिए वह हर हाल में पूरी दिखनी चाहिए। और एक तुम हो कि शहर के इज्जतदारों में शुमार होने के बाद भी

अपनी नाक पर रुमाल रखे हो। ऐसे में लोग क्या समझेंगे?' 'जो समझना हो, समझते रहें। मुझे नाक नहीं, जिंदगी प्यारी है। चलो, अपनी नाक पर रुमाल रखो यार! ये समय बेकार की नाक के दिखावे में न पडने के कि मैं हर चीज से समझौता करने का आदी हूँ, पर क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करता।' 'तो?' 'मैं वक्त से पहले मरना नहीं चाहता बंधु! इसलिए किसी ऐसे हिल स्टेशन पर जा रहा हूँ जहां कम से कम हवा तो क्वालिटी की मिले', कह उन्होंने अपनी जेब से एक रुमाल निकाल मुझे भी अपनी नाक पर रखने को दिया, पर मैं वह रुमाल अपनी नाक पर रखने के बदले ज्यों ही अपनी जेब में डालने को हुआ तो वे मुझ पर गुस्साते बोले, 'हद है यार!

वक्त से पहले मरने का शौक है क्या? मैंने तुम्हें रुमाल जेब में रखने के लिए नहीं, नाक पर रखने के लिए दिया है।' 'मिर! नाक पर रुमाल रखें वे जिनकी नाक कटी हो। नाक बंदतमीज से बंदतमीज की शान होती है। इसलिए वह हर हाल में पूरी दिखनी चाहिए। और एक तुम हो कि शहर के इज्जतदारों में शुमार होने के बाद भी

मानकों के अनुरूप हो? फिर भी क्या हम रिश्तों पर विश्वास नहीं बनाए हैं क्या? ये मानकों के भ्रम बहुत भयानक होते हैं बंधु! पागल से पागल को भी जीने नहीं देते। इसलिए मेरी मानो तो मानकों का मोह छोड़ो और मानकों की पल पल टूटती पट्टी पर वंदे भारत बन आंखें मूंद दोड़ो। बंधु! सच कहूँ, मुझे इस मानक शब्द से सबसे अधिक चिढ़ है। मैं सबसे समझौता कर सकता हूँ, पर इस मानक शब्द से नहीं। कारण, मेरे जैसों का पैदा होने से पहले से ही इस मानक शब्द से छत्तीस का आंकड़ा रहा है। मुझे घटिया हवा पसंद है। मुझे घटिया दोस्त पसंद हैं। मुझे घटिया आटा पसंद है। मुझे घटिया बॉस पसंद है। मुझे घटिया रिश्तेदार पसंद हैं। मुझे घटिया दवा पसंद है। मुझे घटिया विचार पसंद हैं। मुझे घटिया संस्कार पसंद हैं। मुझे घटिया प्यार पसंद है। मुझे मानकहीनता मेरी पहली पसंद है बंधु! मैं अपनी घटिया पसंद की एक से एक चीजें चुन कर उनको गिना रहा था कि इसी बीच पता ही नहीं चला कि कब जैसे वे वहां से वहीं अपना बंधा बिस्तर छोड़ किस ओर खिसक लिए।



# हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर राहत मिलना तय, क्या तंबाकू उत्पादों पर बढ़ेगा टैक्स

परिवहन विशेष न्यूज

व्यक्तिगत रूप से जीवन बीमा की खरीदारी को जीएसटी से मुक्त किया जा सकता है लेकिन सामूहिक रूप से जीवन और स्वास्थ्य बीमा की खरीदारी पर जीएसटी की 18 प्रतिशत दरों को कम कर 12 या पांच प्रतिशत किया जा सकता है। बीमा के रिन्युअल पर दरों में राहत दी सकती है। तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी दर को 28 से 35 प्रतिशत करने की सिफारिश जीओएम ने की है।

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 21 दिसंबर को जैसलमेर में होने वाली बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा की खरीदारी पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी से राहत मिलना तय माना जा रहा है। हालांकि यह राहत पूरी तरह से होगी, इस पर संशय है, क्योंकि जीवन व स्वास्थ्य बीमा की हर प्रकार की खरीदारी को जीएसटी से पूरी तरह मुक्त कर देने पर केंद्र व राज्य दोनों को कई हजार करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा। केंद्र को मिलने वाले राजस्व में भी राज्य की हिस्सेदारी होती है। इसलिए स्वास्थ्य बीमा की एक सीमा तक की खरीदारी को ही जीएसटी से पूरी तरह मुक्त किया जा सकता है। यह सीमा पांच लाख तक की हो सकती है। वहीं, बुजुर्गों की तरह से व्यक्तिगत रूप से स्वास्थ्य बीमा की किसी भी खरीदारी को जीएसटी से मुक्त किया जा सकता है।

बीमा में कितनी मिलेगी राहत?

## क्या सस्ता होगा बीमा प्रीमियम?



व्यक्तिगत रूप से जीवन बीमा की खरीदारी को जीएसटी से मुक्त किया जा सकता है, लेकिन सामूहिक रूप से जीवन और स्वास्थ्य बीमा की खरीदारी पर जीएसटी की 18 प्रतिशत दरों को कम कर 12 या पांच प्रतिशत किया जा सकता है। बीमा के रिन्युअल पर दरों में राहत दी सकती है। इससे पूर्व की जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी समाप्त करने के मामले को मंत्रियों के समूह (जीओएम) के हवाले करके कोई फैसला नहीं लिया गया था। जीओएम को लगभग 150 उत्पाद पर लगाने वाली जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने पर भी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। इन आइटम में फुटवियर और कपड़े भी शामिल हैं। इनमें कई ऐसे आइटम हैं जिनके कच्चे माल और तैयार आइटम

की जीएसटी दरों में काफी विभिन्नता है जिससे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने और देने दोनों में दिक्कत आ रही है।

बीमा राहत पर कब फैसला? सूत्रों का कहना है जीओएम आगामी शनिवार को काउंसिल की बैठक में अपनी रिपोर्ट तो सौंपेगा, लेकिन उस पर काउंसिल तुरंत कोई फैसला नहीं ले सकती है। क्योंकि जीओएम में गिनती के पांच-सात राज्यों के मंत्री शामिल होते हैं। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि अन्य राज्यों को जीओएम का फैसला मंजूर हो। काउंसिल में फैसले के लिए हर राज्य की सहमति जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक, ऐसे में आगामी शनिवार को लगभग 150 आइटम की जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने पर फैसला आना मुश्किल ही है।

दरों को तर्कसंगत बनाने में सबसे बड़ी बाधा यह आ सकती है कि कोई भी राज्य दरों में कमी पर जल्दी सहमति नहीं देगा क्योंकि इससे राजस्व का नुकसान है। जहां जीएसटी दरें बढ़ाने की सिफारिश होगी, उसे आसानी से स्वीकारा जा सकता है क्योंकि इससे राज्यों को राजस्व का फायदा होगा।

तंबाकू उत्पादों पर कर बढ़ाने पर होगी चर्चा तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी दर को 28 से 35 प्रतिशत करने की सिफारिश जीओएम ने की है। इस सिफारिश को मंजूरी मिल सकती है, लेकिन आगामी शनिवार को काउंसिल इस सिफारिश पर राज्यों से पहले चर्चा करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष हैं।

## उच्च पेंशन के लिए ईपीएफओ का अल्टीमेटम, कहा- डेडलाइन के भीतर अपलोड करें डॉक्यूमेंट

हायर सैलरी पर पेंशन का आवेदन करने के लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट किया जा करने का मौका दे रहा है। EPFO का कहना है कि यह कंपनियों को आखिरी मौका दिया जा रहा है क्योंकि कई एक्सटेंशन के बावजूद यह देखा गया है कि अभी बहुत से एप्लीकेशन वॉलेंटरीशन के लिए कंपनियों के पास पेंडिंग पड़े हैं।

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पास हायर पेंशन के लिए 3.1 लाख आवेदन पेंडिंग हैं। EPFO ने अब कंपनियों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सैलरी डिटेल चीजे साझा करने के लिए कंपनियों के लिए 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी है।

EPFO हायर सैलरी पर पेंशन का आवेदन करने के लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने का मौका दे रहा है। EPFO ने कंपनियों से यह भी कहा है कि वे उन 4.66 लाख केस में जवाब दें या जानकारी अपडेट करें, जिनके बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

EPFO ने क्यों बढ़ाई डेडलाइन EPFO का कहना है कि यह कंपनियों को आखिरी मौका दिया जा रहा है, क्योंकि कई एक्सटेंशन के बावजूद यह देखा गया है कि अभी बहुत से एप्लीकेशन वॉलेंटरीशन के लिए कंपनियों के पास पेंडिंग पड़े हैं। कई कंपनियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सैलरी डिटेल अपलोड करने की समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है।

EPFO ने यह सुविधा 26 फरवरी, 2023 को शुरू की गई थी। इसे 3 मई, 2023 तक खत्म हो जाना था। फिर कर्मचारियों और कंपनियों को आवेदन दखिल करने की चार महीने का अतिरिक्त समय दिया गया और

डेडलाइन 26 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई। अब उन्हें आखिरी मौका दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने चार नवंबर 2022 को अपने एक फैसले में कर्मचारियों को हायर सैलरी पर पेंशन देने का विकल्प देने को कहा था। उसकी के बाद EPFO ने यह सारा प्रोसेस शुरू किया था।

पीएफ खाताधारक मिलेगी खास सुविधा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और इम्प्लॉइज स्टेट इन्श्योरेंस कॉरपोरेशन (ईएसआईसी) के सदस्य जल्द ही क्लेम का पैसा ई वॉलेट के जरिये इस्तेमाल कर सकेंगे। एपीएम से पीएफ का पैसा निकालने के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सचिव सुमिता दावरा ने बताया कि बीमित व्यक्तियों और योगदान करने वालों को इसमें काफी दिलचस्पी है कि मैं अपना पैसा कैसे आसानी से निकाल सकता हूँ।

ऑटो सेटलमेंट के मामलों में पैसा बैंक अकाउंट में जाता है और सदस्य मौजूदा समय में किसी भी एपीएम से इसे निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब आप बात कर रहे हैं कि कैसे क्लेम की रकम सीधे वॉलेट या किसी और चीज में जा सकती है। इससे एक तंत्र बनना होगा। इसके लिए हमने बैंकों से बात शुरू कर दी है।

उन्होंने कहा कि हम इसके लिए एक योजना भी बना रहे हैं कि हमें इसे कैसे व्यावहारिक रूप से लागू कर सकते हैं। मौजूदा समय में ईपीएफओ के करीब सात करोड़ सक्रिय सदस्य हैं। ईपीएफओ पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जरूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित कर रहा है। इससे पीएफ खाताधारक कम समय में पीएफ जमा का पैसा निकाल सकेंगे।

## 10 साल से आधार में नहीं बदला पता? परेशानी से बचने के लिए तुरंत करें ये काम

आधार कार्ड फ्री अपडेट आधार कार्ड हमारे लिए बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए या फिर किसी भी सरकारी योजना का लाभ पाने के लिए हमें आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। ऐसे में हमें इसे समय के साथ अपडेट करना होता है। अगर आपने 10 साल से आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट नहीं किया है तो आपको भविष्य में दिक्कत हो सकती है।

पिछले 10 साल से आधार कार्ड अपडेट नहीं किया है तो यह खबर आपके लिए है। फ्री में करें आधार अपडेट भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने फ्री में ऑनलाइन अपडेट (Online Update) करने की सुविधा दी है। आप 14 जून 2025 तक फ्री में आधार अपडेट करवा सकते हैं। इसके बाद आधार अपडेट करने पर शुल्क देना होगा। वैसे तो UIDAI 10 साल में एक बार आधार अपडेट करने की सलाह देता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है।

अब सवाल आता है कि आप फ्री में क्या-क्या अपडेट कर सकते हैं। इसका जवाब है कि फ्री में एड्रेस, मोबाइल नंबर और जी-मेल आईडी अपडेट किया जा सकता है। वहीं, फोटो और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आधार केंद्र जाना होगा। आधार केंद्र जाकर डिटेल्स को अपडेट करने में चार्ज देना होता है। कैसे करें आधार अपडेट (Online Aadhaar Card Update step by step)

स्टेप 1: आपको सबसे पहले UIDAI की ऑफिशियल आईडी (uidai.gov.in) पर जाना है।

स्टेप 2: अब My Aadhaar को सेलेक्ट करें और ड्राफ्ट डान मेनू से 'अपडेट योर आधार' के ऑप्शन को चुनें।

स्टेप 3: अब न्यू पेज ओपन होगा जिसके 'अपडेट आधार डिटेल्स (Online)' को सेलेक्ट करें। अब आधार नंबर और कैप्चा की मदद से लॉग-इन करें।

स्टेप 4: लॉग-इन के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें।

स्टेप 5: ओटीपी भरने के बाद आपको वह ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो आप अपडेट करना चाहते हैं। अब सभी जानकारी को सही करें।

स्टेप 6: सभी डिटेल्स भरने के बाद सबमिट करें और अपडेट से संबंधित डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। इसके बाद सबमिट अपडेट रिक्वेस्ट' पर क्लिक करें।

स्टेप 7: अब आपको रिक्वेस्ट नंबर शो होगा। इस नंबर की मदद से आप अपने अपडेट रिक्वेस्ट को ट्रैक कर सकते हैं।

## दो पिज्जा की कीमत 1 अरब डॉलर हो सकती है? जवाब आपको हैरान कर देगा

परिवहन विशेष न्यूज

बिटकॉइन की कीमत लगातार बढ़ रही है। चार नवंबर को बिटकॉइन का भाव 68 हजार डॉलर था लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद इसमें जोरदार तेजी आई। अब इसकी कीमत 1 लाख डॉलर के पार पहुंच गई है। एक बिटकॉइन 88 लाख की है यानी तकरीबन एक करोड़ की। लेकिन एक शख्स ने 10 हजार बिटकॉइन दो पिज्जा खरीदने के लिए खर्च कर दिए थे।

नई दिल्ली। आप आज की तारीख में दो पिज्जा खरीदना चाहेंगे, या फिर उन पैसों को बचाकर एक दशक बाद 1 अरब डॉलर के मालिक बनना चाहेंगे? आप सोचेंगे कि क्या ही बेतुका सवाल है, कोई भी एक दशक बाद 1 अरब डॉलर ही चाहेगा। लेकिन, एक शख्स ने दो पिज्जा को चुना, शायद बदकिस्मती से। उस शख्स का नाम है, लासजलो हैन्येज (Laszlo Hanyecz)। क्या है 1 अरब डॉलर के पिज्जा की पूरी कहानी?

दरअसल, Laszlo ने क्रिप्टोकॉरेंसी का यूज करके 'रियल वर्ल्ड' में खरीदारी करने

वाले पहले शख्स हैं। उन्होंने 2014 में पापा जॉन्स (Papa Johns) के दो पिज्जा खरीदे थे। उन्होंने पिज्जा का पेमेंट 10,000 बिटकॉइन से किया था। उस समय Laszlo Hanyecz को एक पिज्जा 25 डॉलर यानी करीब 2,117 रुपये का पड़ा था। लेकिन, अब बिटकॉइन की कीमत (Bitcoin Price) 1 लाख डॉलर के पार पहुंच गई है। इस हिसाब से Laszlo Hanyecz ने दो पिज्जा के लिए 1 अरब डॉलर से अधिक चुकाए थे।

बिटकॉइन से पिज्जा खरीदने का अफसोस नहीं

Laszlo Hanyecz की जगह दूसरा शख्स होता, तो शायद 1 अरब डॉलर का पिज्जा खाने का मालाल उसे ज़िंदगीभर रहता। लेकिन, Laszlo Hanyecz कहते हैं, 'मुझे 10 हजार बिटकॉइन से दो पिज्जा खरीदने का कोई पछतावा नहीं है। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी बात है। मैं इस तरह से बिटकॉइन के शुरुआती इतिहास (Bitcoin Early History) का हिस्सा बन गया।'

Laszlo ने बिटकॉइन से कैसे खरीदा था पिज्जा

Laszlo Hanyecz बिटकॉइन के शुरुआती दौर से ही इस डिजिटल करेंसी के



## 1 अरब डॉलर का पिज्जा

मुरीद थे। उन्होंने क्रिप्टो माइनिंग (Crypto Mining) करके काफी बिटकॉइन जुटा ली थी। लासजलो ने 18 मई 2010 को मशहूर क्रिप्टो फोरम bitcoin.org पर एक पोस्ट डाली। उन्होंने पूछा कि क्या कोई 10,000 बिटकॉइन के बदले उन्हें पापा जॉन्स पिज्जा खिलाएगा। उनसे ब्रिटेन के जेरेमी स्टर्डिंघट ने संपर्क किया। जेरेमी ने 10,000 बिटकॉइन के बदले लासजलो के लिए दो पिज्जा ऑर्डर कर दिए।

उस वक़्त भी नुकसान में थे Laszlo Hanyecz

Laszlo Hanyecz बिटकॉइन से पिज्जा खरीदकर उस वक़्त भी घाटे में थे, क्योंकि तब 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू 41 डॉलर थी। वहीं, दो पिज्जा 25 डॉलर में ही आ गया था। लासजलो ने उस वक़्त बिटकॉइन से पहली खरीदारी पर सोशल मीडिया पर शेखी भी बघारी। उन्होंने उन पिज्जा की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर डालीं। बिटकॉइन से यह खरीदारी 22 मई को हुई थी। इसे बिटकॉइन के दिवस (Bitcoin Pizza Day) के तौर पर मनाते हैं।

## आय और लेनदेन में अंतर है तो भर दें संशोधित रिटर्न, आईटीआर फाइल करने से पहले चेक करें एआईएस

परिवहन विशेष न्यूज

आयकर विभाग की तरफ से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आपकी आय और दिए गए टैक्स में अंतर को लेकर कोई एसएमएस या ई-मेल प्राप्त हुआ है तो आप आगामी 31 दिसंबर तक संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। रिटर्न फाइल करने से पहले एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस) को जरूर देख लें। आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।

नई दिल्ली। अगर आयकर विभाग की तरफ से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आपकी आय और दिए गए टैक्स में अंतर को लेकर कोई एसएमएस या ई-मेल प्राप्त हुआ है तो आप आगामी 31 दिसंबर तक संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। संशोधित रिटर्न भरने से पहले विभाग की तरफ से जारी होने वाले अपने एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस) को जरूर देख लें, जिसमें आपकी आय और आपके लेनदेन का विवरण दिया गया है। इसमें दिखाई गई आपकी आय अगर इत स विवरण से मेल नहीं खाती है तो विभाग आपको 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न भरने का मौका दे रहा है। इसी तरह अगर वित्त वर्ष 2021-22 के रिटर्न को लेकर आपको कोई ई-मेल या एसएमएस आया है तो उसके संशोधित रिटर्न के लिए विभाग अगले साल 31 मार्च तक का मौका दे रहा है।

विभाग का कहना है कि अगर आयकरदाता एआईएस में दिए गए विवरण से सहमत नहीं है तो वह इस संबंध में अपना फीडबैक भी पोर्टल पर दे सकता है। विभाग का कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एआईएस में अधिक मूल्य वाले लेनदेन दिख



रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई आईटीआर दाखिल नहीं किया है या फिर उस ट्रांजेक्शन के हिसाब से अपनी आय को नहीं दर्शाया है। विभाग ने कहा है कि लोग रिटर्न दाखिल करने के लिए मौके का फायदा उठा सकते हैं और देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग पिछले कुछ सालों से नॉन फाइलर मानिट्रिंग सिस्टम के जरिये आय की तुलना में कम टैक्स भरने वालों पर भी कड़ी नजर रख रहा है। विभाग अपनी प्रणाली से उन लोगों को भी पहचान कर रहा है, जिन्होंने पिछले वर्ष सालों में घूमने-फिरने के साथ ज्वैलरी व अन्य खरीदारी में भारी नकदी का इस्तेमाल किया है, लेकिन वे कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं।

आयकर विभाग ने जारी किया FA Q

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार आयकर विभाग ने कहा है कि 22 जुलाई, 2024 तक लॉन्च सभी अपीलें (चाहे उनका निपटारा कर दिया गया हो या उन्हें वापस ले लिया गया हो) विवाद से विश्वास योजना के तहत पात्र होंगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने विवाद से विश्वास योजना, 2024 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का एक नया सेट जारी किया है, जिसके तहत विवाद समाधान योजना का लाभ उठाने के इच्छुक करदाताओं को 31 दिसंबर तक घोषणापत्र दाखिल करना जरूरी है।

सीबीडीटी ने कहा कि उसे योजना के बारे में कई प्रश्न प्राप्त हुए हैं और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जागरूकता पैदा करने में मदद

करेंगे। सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई करदाता विवाद से विश्वास योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र था और उसकी अपील 22 जुलाई, 2024 तक लॉन्च थी (भले ही करदाता द्वारा घोषणा दाखिल करने से पहले अपील का निपटारा कर दिया गया हो) तो ऐसे मामलों को योजना के तहत निपटान के लिए पात्र माना जाएगा और विवादित कर की गणना उसी तरह से की जाएगी जैसे कि अपील का निपटारा होना बाकी है।

सीबीडीटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि विवादित राशि की कम दर भुगतान की पात्रता के लिए 31 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले घोषणा दाखिल करना जरूरी है न कि उस तिथि से पहले भुगतान करना।

## कृषि में ड्रोन का होगा ज्यादा इस्तेमाल, महिलाओं को भी मिलेगा रोजगार के अवसर



परिवहन विशेष न्यूज

प्रखर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह प्रोजेक्ट 1500 एकड़ से अधिक भूमि में स्थानीय सरकारी निकायों के साथ मिलकर शुरू हुआ है। कंपनी ने हाल ही में हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के साथ साझेदारी की है। कंपनी का लक्ष्य है कि वह साल 2027 तक 5000 महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करें।

नई दिल्ली। एग्रीकल्चर सेक्टर में विकास को बढ़ावा देने के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। कृषि क्षेत्रों में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रखर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ने इसके इस्तेमाल और उसके फायदे के बारे में बताने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह प्रोजेक्ट 1500 एकड़ से अधिक भूमि में स्थानीय सरकारी निकायों के साथ मिलकर शुरू हुआ है।

पैदा होंगे नए रोजगार कंपनी का लक्ष्य इस एग्रीकल्चर सेक्टर को विकसित के साथ महिलाओं को रोजगार के अवसर देना भी है। कंपनी ने लक्ष्य तय किया है कि इस प्रोजेक्ट से साल 2027 तक 5,000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए हाल ही में प्रखर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के साथ साझेदारी की। इस साझेदारी में प्रखर में प्रखर को जमान को बढ़ावा देने के लिए 1,250 एकड़ से ज्यादा भूमि

में ड्रोन छिड़काव का प्रदर्शन किया। इसके आगे उन्होंने कहा कि प्रखर एकमात्र घरेलू ड्रोन निर्माता कंपनी है। इसने स्वदेशी ड्रोन और एआई आधारित मॉडल और 3डी प्रिंटेड जैसे अन्य महत्वपूर्ण कंपोनेंट के साथ ड्रोन को मैनुफैक्चर किया है। कंपनी ने ड्रोन से होने वाले संभावित हमलों को पहचान भी किया है और इसके बचाव में भू-स्थानिक इंटेलेजेंस आधारित प्रणाली विकसित की है। इसके अलावा कंपनी ने एआई-एनालिटिक्स क्षमताओं के साथ सुरक्षित लाइव-स्ट्रीमिंग टूल, सामरिक और निगरानी संचालन के दौरान संवेदनशील डेटा को सिक्योर भी रखा है।

प्रखर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के बारे में प्रखर ड्रोन और तकनीक से संबंधित इन्क्यूबेटर बनाती है। यह कंपनी मेक इन इंडिया मिशन का नेतृत्व कर रही है। ड्रोन का उपयोग कई देशों में कृषि क्षेत्र में किया जा रहा है। ड्रोन का उपयोग काफी फायदेमंद रहता है। इसके फायदे को लेकर इंडिया ब्रांड इन्विवटी फाउंडेशन (आईबीईएफ) ने कहा कि ड्रोन का उपयोग सटीक खेती, फसल निगरानी, मिट्टी विश्लेषण, सिंचाई प्रबंधन और प्लांटिंग कार्यों में किया जा सकता है।

प्रखर ने स्वदेशी कामिकेज ड्रोन आधारित एटी-ड्रोन तकनीक विकसित किया है। इसके अलावा उसने 10,000 से अधिक युवाओं को ड्रोन में कौशल प्रशिक्षण भी दिया है।

## वन नेशन-वन इलेक्शन बिल अब JPC के पास, अगर 2025 में पास हुआ तो कब होंगे एक साथ चुनाव?

केंद्र सरकार ने एक देश-एक चुनाव से संबंधित 129वां संविधान संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया गया है। यह विधेयक जेपीसी को भेजा जाएगा। अगर विधेयक 2026 में पास होता है तो चुनाव आयोग को साल 2029 तक तैयारी करनी होगी। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि एक देश-एक चुनाव पूरी तरह लागू होने में 2034 तक का समय लग सकता है



**नई दिल्ली।** 'एक देश-एक चुनाव' की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच इससे संबंधित संविधान का 129वां संशोधन विधेयक और इससे जुड़ा एक अन्य विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया। तब विपक्ष ने इस बिल को तानाशाही करार देते हुए बिल को संविधान संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने की मांग की। केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन के लिए दो तिहाई बहुमत जुटाने की चुनौती और विपक्ष की मांग के मद्देनजर दोनों विधेयकों को जेपीसी में भेजने पर हामी भर दी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब बिल मंत्रिमंडल में चर्चा के लिए आया था, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे JPC भेजने की बात कही। अब दोनों विधेयक - संविधान का 129वां संशोधन और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल जेपीसी को भेजे जाएंगे।

सवाल ये है कि संसद का मौजूदा सत्र 20 दिसंबर तक है। ऐसे में संसद के इस सत्र में बिल पास नहीं होंगे। संयुक्त संसदीय समिति की मंजूरी मिलने के बाद अगर बिल संसद में बिना परिवर्तन

पास हो गए तो यह कब तक अमल आएगा?

**कैसे होगा जेपीसी का गठन?**

संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे। किस पार्टी के कितने सदस्य होंगे, यह संख्या संसद में पार्टियों की ताकत के हिसाब से तय होगी। ऐसे में सबसे बड़ी पार्टी होने से सबसे ज्यादा सदस्य और अध्यक्ष भाजपा से हो सकता है।

**जेपीसी क्या करेगी?**

एक देश-एक चुनाव से संबंधित आठ पेज के इस बिल में जेपीसी को अच्छा खासा होमवर्क करना होगा। संविधान के तीन अनुच्छेदों में परिवर्तन करने और एक नया प्रावधान जोड़ने की पेशकश की गई है। दरअसल, अनुच्छेद 82 में नया प्रावधान जोड़कर राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटेड तरीख पर फैसले की बात कही गई है। बता दें कि अनुच्छेद 82 जनगणना के बाद परिसीमन के बारे में है।

**जेपीसी कब देगी रिपोर्ट?**

संविधान का 129वां संशोधन और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयकों को अंतिम रूप देने में करीब-करीब पूरे 2025 लग सकता है। ऐसा होता है तो ये दोनों बिल सदन में 2026 में फिर

जाएंगे।

अगर विधेयक बहुमत जुटाकर बिल पास करवा लिए गए तो निर्वाचन आयोग के पास 2029 की तैयारी के लिए सिर्फ दो साल साल बचेंगे। एक देश-एक चुनाव के तहत सभी राज्यों और पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए यह समय पर्याप्त नहीं है।

**क्या कोई डेडलाइन तय है?**

नहीं, अभी तक विधेयक में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि यह कब से लागू होना है। केंद्र सरकार ने इसे लागू करने का अधिकार अपने पास रखा है। राष्ट्रपति की अधिसूचना का समय भी स्पष्ट नहीं किया है।

**विधेयक पास होने के बाद क्या होगा?**

ये सबसे अहम सवाल है कि साल 2029 के चुनाव के बाद राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर लोकसभा की पहली बैठक की तारीख तय करेंगी। चुनाव होंगे और फिर पांच साल लोकसभा का फुल टर्म 2034 में पूरा होगा।

इसके साथ ही सभी विधानसभाओं का कार्यकाल पूरा मान लिया जाएगा, तब जाकर चुनाव एक साथ कराए जा सकेंगे।

**तैयारी में कितना वक्त चाहिए?**

अगर अभी तक की प्रक्रिया देखी जाए तो बुनियादी जरूरतों के हिसाब से 2034 की टाइमलाइन मेल खाती है। चुनाव आयोग को एक देश एक चुनाव के लिए कम से कम 46 लाख ईवीएम चाहिए।

अभी चुनाव आयोग के पास सिर्फ 25 लाख मशीनें हैं। मशीनों की एक्सपायरी 15 साल है। ऐसे में दस साल में 15 लाख मशीनों की उम्र पूरी हो जाएगी। मशीनों के इंतजाम में भी 10 साल का वक्त लग सकता है।

## रेलवे पर कोहरे की मार: कई प्रमुख ट्रेनें चल रही लेट, देखें देरी से चलने वाली ट्रेनें की पूरी लिस्ट

टंड-प्रदूषण के कारण रेल यात्रियों की परेशानी जारी है। दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। पूर्व और दक्षिण दिशा से आने वाली ट्रेनें सबसे ज्यादा विलंब से चल रही हैं। देरी से दिल्ली पहुंचने के कारण कई ट्रेनें के प्रस्थान समय में बदलाव किया गया है। आनंद विहार टर्मिनल-सहरसा गरीब रथ विशेष आनंद विहार टर्मिनल-मुजफ्फरपुर सुपरफास्ट विशेष सहित चार ट्रेनें विलंब से रवाना होंगी।

**नई दिल्ली।** सर्दी व प्रदूषण के बीच रेल यात्रियों की परेशानी बनी हुई है। बुधवार को भी दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। पूर्व व दक्षिण दिशा से आने वाली ट्रेनें अधिक विलंब से चल रही हैं। देरी से दिल्ली पहुंचने के कारण कई ट्रेनें के प्रस्थान समय में बदलाव किया गया है।

आनंद विहार टर्मिनल-सहरसा गरीब रथ विशेष, आनंद विहार टर्मिनल-मुजफ्फरपुर सुपरफास्ट विशेष, सहित चार ट्रेनें विलंब से रवाना होंगी।

**देरी से चलने वाली प्रमुख ट्रेनें**

राजगीर-नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस-चार घंटे  
चेन्नई-नई दिल्ली तमिलनाडु एक्सप्रेस-बाई घंटे

बरोनी-नई दिल्ली हम्मसफर विशेष (02563)-चार घंटे  
विशाखापत्तनम-नई दिल्ली एपी एक्सप्रेस-चार घंटे

साई नगर शिरडी-कालका सुपरफास्ट एक्सप्रेस-साढ़े तीन घंटे  
मुजफ्फरपुर-आनंद विहार टर्मिनल सुपरफास्ट विशेष (05283)- सवा पांच घंटे  
मुजफ्फरपुर-आनंद विहार टर्मिनल सुपरफास्ट विशेष (05219)- पौने सात घंटे

पुरी-योगनगरी ऋषिकेश उल्कल एक्सप्रेस- तीन घंटे

योगनगरी ऋषिकेश-पुरी उल्कल एक्सप्रेस- बाई घंटे

राजेंद्र नगर-फिरोजपुर हम्मसफर विशेष (04651)-तीन घंटे  
धनबाद-जम्मूतवी गरीब रथ विशेष (03309)-सवा चार घंटे

दिल्ली से देरी से रवाना होने वाली मुख्य ट्रेनें

आनंद विहार टर्मिनल-सहरसा गरीब रथ विशेष (05578) -3.05 घंटे

आनंद विहार टर्मिनल-मुजफ्फरपुर सुपरफास्ट विशेष (05284)-चार घंटे

आनंद विहार टर्मिनल-मुजफ्फरपुर सुपरफास्ट विशेष (05220)- पांच घंटे

हजरत निजामुद्दीन-दुर्ग हम्मसफर-एक घंटा  
धुंध की मोटी चादर में लिपटा रहा दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली-एनसीआर बुधवार को धुंध की मोटी चादर में लिपटा रहा और लगातार तीसरे दिन वायु गुणवत्ता रंगभीर श्रेणी में रही। वहीं, दिल्ली एनसीआर में टंड बढ़ गई है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सुबह 7:15 बजे 442 दर्ज किया गया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के कई क्षेत्रों में 400 से 500 के बीच का स्तर दर्ज किया गया। पूरे क्षेत्र में दृश्यता काफी कम हो गई थी, दृश्यता 300 मीटर तक गिर जाने के बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर कम

दृश्यता प्रक्रियाएं लागू की गईं।

**गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया एक्यूआई**  
दिल्ली के प्रमुख क्षेत्रों में खतरनाक AQI स्तरों की सूचना दी गई, जिसमें आनंद विहार (481), अशोक विहार (461), बुराड़ी क्रॉसिंग (483) और नेहरू नगर (480) शामिल हैं। अलीपुर, जहांगीरपुरी और मुंडका जैसे अन्य प्रमुख स्थानों में क्रमशः 443, 469 और 473 के AQI स्तर दर्ज किए गए। 1263 पर, गुरुग्राम 392 और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद 390, ग्रेटर नोएडा 330, और नोएडा 364 पर रहा।

गंभीर वायु प्रदूषण टंड के मौसम की स्थिति के साथ मेल खाता है, क्योंकि दिल्ली-एनसीआर में 100 प्रतिशत और 66 प्रतिशत के बीच आद्रता के स्तर में उतार-चढ़ाव हुआ। कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। शांत हवाओं और उच्च आद्रता ने शहर के विभिन्न हिस्सों में हल्का कोहरा पैदा किया, जिससे प्रदूषण का स्तर और खराब हो गया।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में धुंध की स्थिति बनी रह सकती है, जिससे शीतलहर के तेज होने की संभावना है। सुबह-सुबह दृश्यता कम होने और सर्द परिस्थितियों का सामना करने की उम्मीद है। स्थिति प्रदूषण नियंत्रण उपायों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है क्योंकि निवासी खतरनाक वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य जोखिमों से जूझते हैं।

अधिकारियों ने प्रदूषण रोधी उपायों को सख्ती से लागू करने का आग्रह किया है और निवासियों, विशेष रूप से कमजोर समूहों को बाहरी गतिविधियों को सीमित करने की सलाह दी है। सर्दी बढ़ने और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के साथ, दिल्ली-एनसीआर में धुंध के साथ लड़ाई एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।

## मुख्यमंत्री का शाहपुरा दौरा : हर वर्ग और हर जन की सेवा ही राज्य सरकार का संकल्प

लोककल्याणकारी फैसलों से पूरे राज्य में उत्साह का माहौल - मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा - महाराणा प्रताप और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से मिलती है प्रेरणा  
परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

**शाहपुरा/जयपुर।** मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने पूर्ण लगन एवं समर्पण से कार्य करते हुए एक वर्ष उत्कृष्टता के साथ पूरा किया है। इस एक साल में राज्य सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और प्रदेश के हर वर्ग और हर जन की सेवा को ही संकल्प मानकर निरंतर काम कर रही है। बुधवार को शाहपुरा में निर्मूर्ति सिकिल पर शहीदों को माल्यापण, केंद्रीय बस स्टैंड पर शूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप की मूर्ति तथा उम्मेद सागर पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की

मूर्ति का अनावरण किया।

इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप शौर्य, पराक्रम और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। वे केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश-दुनिया में भी लोगों के स्रोत हैं। साथ ही, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी एक महान विचारक तथा प्रखर शिक्षाविद् होने के साथ-साथ एक कुशल संगठनकर्ता थे। आज इन विभूतियों की प्रतिमाओं के अनावरण से जनमानस इनके जीवन से परिचित होंगे जिससे उनमें देशभक्ति की भावना का संचार होगा। राज्य सरकार ने राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित कर प्रदेश के विकास और समृद्धि की नींव रख दी है। इस समिट में 35 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के एमओयू हुए हैं, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही हमारे युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जयपुर में



आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने राजस्थान को एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य

योजना, मा वाउचर योजना की शुरुआत तथा रामाश्रम वार्ड तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना कर राज्य के निवासियों को स्वस्थ एवं सुखी जीवन की नई राह प्रदान की है। पिछले एक साल के

दौरान राज्य सरकार के लोककल्याणकारी फैसलों से पूरे राज्य में उत्साह का माहौल बना है। प्रदेश में अच्छे मानसून और पानी से लबालब भरे बांधों ने इस उत्साह को और ऊंचाई दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाएं और केंद्रों के विकास के आगे ले जाने का रोडमैप है, बल्कि इनमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का विजन भी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शाहपुरा जिले के लिए भी कई महत्वपूर्ण बजट घोषणाएं की हैं और उन्हें तेजी से साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। लगभग 194 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण, सुदृढीकरण तथा चौड़ाईकरण कावाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका जहाजपुर में फुल एवं सक्की मंडी, गुद्दा (जहाजपुर) में 33/11 केवी जीएसएस, शाहपुरा में ट्रोमा सेंटर, अमरागढ़ एवं सरदार नगर उप स्वास्थ्य केंद्रों का पीएचसी तथा जहाजपुर पीएचसी का उप जिला

चिकित्सालय में क्रमोन्नयन, जिला अस्पताल शाहपुरा के भवन का निर्माण, बनेड़ा में खेल स्टेडियम, शाहपुरा में खेल अकादमी, कोटडी में नवीन महाविद्यालय, जहाजपुर में कन्या महाविद्यालय, पीपलुंद में औद्योगिक क्षेत्र, पण्डेर में औद्योगिक पार्क, शाहपुरा जिले में आमजन की सहभागिता से एक 'मातृ वन' की स्थापना, काले हिरणों के संरक्षण हेतु आशोप क्षेत्र को आखेट निषिद्ध व कंजवेंशन रिजर्व क्षेत्र घोषित करने, जहाजपुर में जनजाति छात्रावास तथा गाडोली में नवीन पशु उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने सहित विभिन्न विकास कार्य प्रस्तावित व प्रगतिरत हैं।

इस दौरान विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल, महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री डॉ. मंजू बाधमार, विधायक लालाराम बैरवा, गोपी चन्द मीणा, पुष्पेन्द्र सिंह राणावत सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

## चाँकाने वाली रिपोर्ट: बांग्लादेश के घुसपैटियों का सुरक्षित ठिकाना बनी दिल्ली

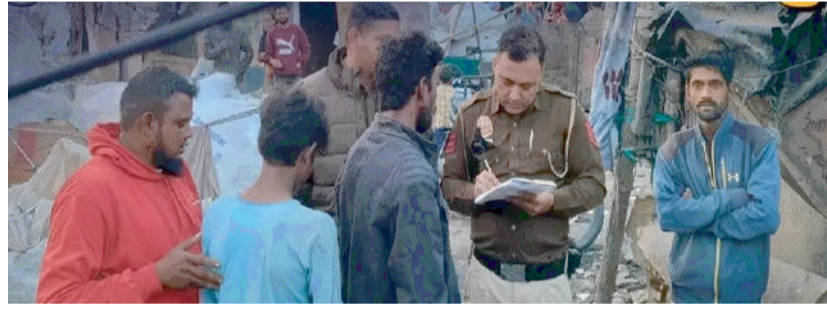
बांग्लादेशी घुसपैटियों ने दिल्ली को अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया है। ये लोग देह व्यापार से लेकर वोट बैंक तक में अपनी पैठ बना चुके हैं। राजधानी के कई इलाकों में इनकी बस्तियां बस गई हैं। ये लोग दिल्ली के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इस रिपोर्ट में पट्टि आखिर ये लोग कैसे राजधानी में आकर आसानी से बस जाते हैं।

**नई दिल्ली।** राष्ट्रीय राजधानी राजनीति के साथ रोजगार के लिए भी बड़ा केंद्र है। बांग्लादेश के घुसपैटिये इसी लालच में भारत की राजधानी तक आने के लिए ठेकेदारों से सौदा करते हैं। बांगाल व असम में कागजी तौर पर मजबूत बनाने के बाद ठेकेदार ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना कर देते हैं।  
बताया गया कि वर्षों से चल रहे इस सिलसिले से राजधानी में इनके कई ठिकाने बन चुके हैं। अपने ठेकेदार व एजेंटों के माध्यम से ये सीधे उन्हीं ठिकानों पर पहुंचते हैं। कुछ समय बिताते और यहां भाषा को जल्द सीखने के साथ शुरुआत कूड़ा बिनाने से करते हैं। धीरे-धीरे अपने आसपास श्रमिक के तौर पर काम शुरू करते हैं। समय के साथ वोट बैंक बनकर इन्हें राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त हो जाता है।

वर्षों से दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैटियों का आने का क्रम जारी है। ऐसे में दिल्ली में धीरे-धीरे इनका फैलाव हर हिस्से में हो चुका है और इनके यहीं पर परिवार भी बस चुके हैं। सस्ता श्रम होने के कारण दिल्लीवाले भी यह जानने की जहमत में नहीं पड़ते कि सामने वाला कौन है। इसी का फायदा उठाकर ये लोग खुद को असम और बांगाल का निवासी बताकर गाड़ी पोंछने, प्रेस करने, कूड़ा बिनाने, दुकानों पर छोटे-मोटे काम करने लगाते हैं।

संगठित रहने और एक मुखाया होने के कारण नेताओं को इनमें वोट बैंक भी दिखाता है। समय के साथ भ्रष्ट सिस्टम और क्षेत्रीय नेताओं की सरपरस्ती में इनका मतदाता पहचान पत्र भी बन जाता है। इनका फैलाव दिल्ली के साथ ही पड़ोस के शहरों फरीदाबाद, गाजियाबाद में अधिक है।

बताया गया कि पहचान के दस्तावेज से लैस होकर ये देश में गरीबी उथान के लिए मिलने वाली सुविधाओं के भी हकदार बन जाते हैं। ये सुविधा और अपनी आर्थिक स्थिति बदलने का लालच इन्हें लगातार दिल्ली की ओर आने के लिए आकर्षित करता है।  
ज्यादा कमाई के चक्कर में धीरे-धीरे दिल्ली के ड्रमस माफिया के लिए ये पैडलर भी बन जाते हैं। ये



तस्करों का ड्रमस दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाते हैं। इनकी बस्तियों में यह हर समय उपलब्ध भी रहता है। इसके साथ ही ये हत्या, लूट, डकैती, चोरी जैसी आपराधिक वारदात में लिप्त होते हैं।

**बस्तियों में संचालित किया जा रहा देह व्यापार का अड्डा**

इनकी बस्तियों में देह व्यापार का अड्डा भी संचालित किया जा रहा है। वर्षों से दिल्ली में रहने के दौरान इनकी अगली पीढ़ियां भी तैयार हो गई हैं। पूर्वी दिल्ली में सीमापुरी, दक्षिण दिल्ली में शाहीन बाग, निजामुद्दीन, कालिंदी कुंज, मदनपुर खादर, पश्चिमी दिल्ली में समालका, मुंडका और बाहरी दिल्ली स्थित नरेला,

बवाना में इनकी कई बस्तियां बस गई हैं।

सीमापुरी में इनकी संख्या 40 हजार के अधिक बताई जाती है। यहां एक के बाद एक तीन बड़ी-बड़ी झुग्गियां आकार ले चुकी हैं।

**ये राजधानी के लिए बन सकते हैं बड़ा खतरा**

दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त एसएन श्रीवास्तव का कहना है कि दिल्ली में घुसपैटियों को आसानी से छोटा-मोटा रोजगार मिल जाता है। इसलिए ये यहां रुख करते हैं। ये राजधानी के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं। ये आतंकियों का भी मोहरा बन सकते हैं। इनसे सतर्क रहने के साथ पहचान सुनिश्चित करने की जरूरत है।

## आज के युवा अपने दुख से ज्यादा दूसरों के सुख से अधिक दुखी हैं: अनिल सक्सेना

। भारतीय ज्ञान परंपराओं को आधुनिक शिक्षा में एकीकृत करने पर राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम।।

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

**भोलवाड़ा।** स्थानीय संगम विश्वविद्यालय, भोलवाड़ा, राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित पांच दिवसीय संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) का भव्य शुभारंभ किया। आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रणालियों को एकीकृत करना- एनईपी-2020 परिप्रेक्ष्य विषय पर आधारित कार्यक्रम में एआईयू-एडीसी (अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शैक्षणिक और प्रशासनिक विकास केंद्र) के तत्वाधान में 16 से 20 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देशभर से शिक्षाविद, विशेषज्ञ और प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। तीसरे दिन मुख्य वक्ता के रूप में अनिल सक्सेना, वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार ने भारतीय साहित्य, संस्कृति और ज्ञान परंपरा विषय पर

अपने विचार रखे। अनिल सक्सेना ने बताया कि आज के युवा भारतीय संस्कृति से जुड़े, ज्ञान परंपरा को समझे तथा शिक्षा में संस्कृति के समावेश को समझाया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से युवा पीढ़ी सकारात्मक के साथ नकारात्मकता में भी जा रही है जिसे रोकने को कहा। महाराष्ट्र, रामायण से मिलने वाली सीख पर ध्यान देना चाहिए तथा वेदों, धर्मों के सकारात्मक प्रभाव को मानव जीवन में अपनाने के प्रयास में बल दिया। गुरु शिष्य परंपरा को समझाया। कुलपति प्रो. करुणेश सक्सेना ने कहा कि जीवन में अगर सफल होना है तो कोई भी एक अखबार जरूर पढ़े, उसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा ने न केवल प्राचीन समय में अत्यधिक प्रभावशाली थीं, बल्कि आज के युग में भी उनका उपयोग आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को दिशा देने में किया जा सकता है। उप कुलपति प्रोफेसर मानस रंजन पाणिग्रही ने पांच



दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। कुलसचिव प्रोफेसर राजीव मेहता ने कहा कि यह पहल एनईपी-2020 के उद्देश्यों को पूरा करनी की दिशा में

एक महत्वपूर्ण योगदान है। कार्यक्रम के अंत में प्रोफेसर प्रीती मेहता डायरेक्टर और नोडल ऑफिसर ने धन्यवाद ज्ञापित किया।